नई दिल्ली । गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026
बैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक :114 / मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
नई दिल्ली संस्करण
सिर्फ पत्रकारिता...

vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwakesari_news

आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल फीफा और एएफसी ने अफगान महिलाओं को...
@ विचार उच्च शिक्षा में 'मार्केट फार लेमन्स'
@ व्यापार भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा...

एग्जिट पोल → बंगाल- 5 में भाजपा, 2 में टीएमसी : असम में भाजपा, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी,केरल में 10 साल बाद यूडीएफ की सरकार, पुडुचेरी- एनडीए को बढ़त

एजेंसी ■ नई दिल्ली

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के नतीजों ने राजनितिक माहौल को गरमा दिया है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों (7 एजेंसी) के आकड़े अलग-अलग तस्वीर पेश कर रहे है। जिससे सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी पार्टियों के बीच दावे-प्रतिदावे तेज हो गए है । वही जिन जगहो पर जिन दलों की सरकार बनते दिख रही है वहा के कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल दिखलाई पड़ने लगा है। कही सत्ता बरकरार रहने के सकेंत मिल रहे है, तो कही बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। हालाकि एग्जिट पोल्स की सटीकता व विश्वनियता पर हमेशा सवाल उठते रहे है। इसलिए अंतिम फ सला तो मतगणना के दिन स्पष्ट होगा सर्वे एजेंसियों के इन नतीजों ने सियासी चर्चाओं में हलचल मचा दी है। यही नही रिजल्ट नई दिशा में मिलते दिखलाई दे रहें है।

बंगाल-5 में भाजपा सरकार , 2 में टीएमसी

एजेंसी ■ कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान पूरा हो गया, जिसके बाद बुधवार शाम को एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है, लेकिन अलग-अलग एजेंसियों के सर्वे में तस्वीर पूरी तरह बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ एग्जिट पोल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं, तो कुछ सर्वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पहली बार बंगाल में सरकार बनाते हुए बता रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी के एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य दलों के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। पीपुल्स पल्स के सर्वे में टीएमसी को 117 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा 146 से 161 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई गई है। अन्य दलों को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पी-मार्क के सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एबीपी न्यूज-सी वोटर के एग्जिट पोल में भी टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 150 से 175 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी के अनुमान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 99 से 127 सीटें, भाजपा को 142 से 171 सीटें, कांग्रेस को तीन से पांच, लेफ्ट गठबंधन को दो से तीन और अन्य के खाते में एक सीटें जाने का अनुमान है । प्रजा पोल के सर्वे के अनुसार, टीएम को 85 से 110 सीटें, भाजपा को 178 से 208 सीटें और अन्य को 0 से पांच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

पुडुचेरी- एनडीए को बढ़त का अनुमान, कांग्रेस रह गई पीछे

पुडुचेरी । केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सभी 30 सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया गया। मतगणना 4 मई को होगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 17 सीटों की जरूरत होगी। इस बीच अब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं।पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं।

जेवीसी के एग्जिट पोल में भी भाजपा गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है।

असम में फिर भाजपा की वापसी, 88 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद

पूर्वोत्तर के राज्य असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है। शाइनिंग इंडिया के सर्वे में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है।

शाइनिंग इंडिया के सर्वे में भाजपा को 126 में से 88 प्लस सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं, कांग्रेस को लगभग 31 सीटें, यूडीएफ को लगभग 4, और अन्य को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं, 19 सीटों पर नजदीकी मुकाबला बताया गया है ।इनिंग इंडिया के सर्वे के अनुसार, अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 45.8 प्रतिशत मिल सकता है। वहीं, कांग्रेस को 37.5 प्रतिशत, यूडीएफ को 3.6 प्रतिशत, और अन्य को 8.9 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, जबकि 4.2 प्रतिशत वोटों को साइलेंट बताया गया है।

तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के आसार , 124 सीटें मिलने की उम्मीद

दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ गया है। शाइनिंग इंडिया सर्वे में डीएमके की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। शाइनिंग इंडिया सर्वे में डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 124 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं, एआईएडीएमके गठबंधन को 103 सीटें मिलने की उम्मीद है। जबकि, अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को भी 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। शाइनिंग इंडिया सर्वे में डीएमके गठबंधन को 38.6 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही गई है। जबकि, बहुत कम अंतर के साथ एआईएडीएमके 37.3 प्रतिशत के आंकड़े को छू सकती है। इसके साथ ही टीवीके को भी 16.2 प्रतिशत वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर अन्य को 3.9 प्रतिशत और साइलेंट को 4 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल चुनाव: दूसरे चरण में रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान

एजेंसी ■ कोलकाता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 89.99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।

दिन भर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं और लोगों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सुबह के मुकाबले दोपहर बाद मतदान में तेजी आई। दोपहर 1 बजे तक पहले छह घंटों में 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जो तीन बजे तक बढ़कर 78.68 प्रतिशत पहुंच गया। इसके बाद अंतिम घंटों में भी मतदाताओं की सक्रियता बनी रही, जिससे कुल मतदान प्रतिशत लगभग 90 फीसदी के करीब पहुंच गया।

जिलेवार आंकड़ों में कई क्षेत्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पूर्व बर्धमान में सबसे अधिक 92.46 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अलावा हुगली में 90.34 प्रतिशत और नादिया में 90.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अन्य जिलों में भी मतदाताओं की भागीदारी काफी प्रभावशाली रही।

ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, किंग चार्ल्स भी इससे सहमत हैं : ट्रंप

एजेंसी ■ वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किंग चार्ल्स तृतीय के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध का जिक्र किया। दरअसल, ईरान के साथ यह लड़ाई की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच भी तनाव देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'हम अभी मिडिल ईस्ट में थोड़ा काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और दावा किया कि चार्ल्स भी इससे सहमत हैं। उन्होंने कहा, 'हमने उस खास दुश्मन को मिलिट्री से हरा दिया है और हम उस दुश्मन को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और इस मामले पर चार्ल्स मुझसे भी अधिक सहमत हैं। कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग में बोलते हुए। चार्ल्स ने कहा कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक संघर्ष के समय दोनों देश बहुत अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। जिसके नतीजे दोनों समाजों पर महसूस किए जा रहे हैं।

विधानसभा एग्जिट पोल

राज्य	पार्टी	Peoples Pulse	Axis My India	Chanakya Strategies	MATRIZE
असम सीटे : 126	BJP+	68-72	88-100	88-98	85-95
	INC+	22-26	24-36	22-32	25-32
	Other	7-15	0-3	3-5	6-12
केरलम सीटे : 140	LDF	55-65	49-62	58-64	60-65
	UDF	70-75	78-90	72-80	70-75
	NDA	3-5	0-3	0-0	0-0
	Other	2-4	0-0	0-7	5-9
तमिलनाडु सीटे : 234	AIADMK+	65-80	22-32	50-65	122-132
	DMK+	125-145	92-110	145-160	87-110
	Other	20-30	98-120	18-26	10-18
पश्चिम बंगाल सीटे : 294	TMC	178-189	0-0	130-140	125-140
	BJP	95-110	0-0	150-160	146-161
	INC	1-3	0-0	0-0	0-0
	LEFT	0-1	0-0	0-0	0-0
	OTHER	0-0	0-0	6-10	6-10
पुडुचेरी सीटे : 30	BJP+	16-19	16-20	0-0	0-0
	INC+	10-12	6-8	0-0	0-0
	Other	1-2	3-7	0-0	0-0

केरल में यूडीएफ की जीत के संकेत, 140 में से 83 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद

केरल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। शाइनिंग इंडिया के सर्वे में केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की धमाकेदार जीत नजर आ रही है। शाइनिंग इंडिया के सर्वे के अनुसार, केरल चुनाव में यूडीएफ को 140 सीटों में से लगभग 83 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ को 54 और एनडीए को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं, 21 सीटों पर नजदीकी मुकाबले के आसार हैं।

शाइनिंग इंडिया सर्वे के अनुसार, यूडीएफ को 43.6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एलडीएफ को 38.2 प्रतिशत और एनडीए को 13.5 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं, 1.3 प्रतिशत वोट अन्य के खाते में जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही 3.4 प्रतिशत वोटों को साइलेंट बताया गया है।

गाजियाबाद हाईराइज सोसायटी में लगी भीषण आग

एजेंसी ■ गाजियाबाद

गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी फ्लैटों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में 9वें, 10वें और 11वें तल तक पहुंच गई और पूरी बिल्डिंग में काला जहरीला धुआं भर गया।

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 8:48 बजे फायर स्टेशन वैशाली को घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम पांच दमकल गाड़ियों के साथ मौके के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर स्थिति बेहद गंभीर पाई गई, जहां कई फ्लैटों में आग धधक रही थी और कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे। आग की

भयावहता को देखते हुए तुरंत अन्य फायर स्टेशनों से भी सहायता मांगी गई।

इसके अलावा गौतमबुद्धनगर से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और अतिरिक्त दमकल वाहन भी बुलाए गए। कुल मिलाकर 17 दमकल गाड़ियां, वाटर बाउजर और 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग की टीमों ने दो हिस्सों में बंटकर एक ओर आग बुझाने का काम शुरू किया, वहीं दूसरी ओर सीढ़ियों के जरिए फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया ।रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगभग 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल थे, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इमारत में फैले घने धुएं और अफरा-तफरी के बीच लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी ।दमकल कर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए पूरी बिल्डिंग को खाली कराया। कई फ्लैटों के दरवाजे बंद होने के कारण रेस्क्यू कटर की मदद से दरवाजे काटकर अंदर पहुंचा गया और आग को बुझाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट: छात्राओं ने फिर मारी बाजी

एजेंसी ■ रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीजीबीएसई) ने बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ डिजीलॉकर पोर्टल पर कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा 2026 के परिणाम जारी दिए।

इस वर्ष छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 77.15 और 12वीं बोर्ड परीक्षा का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 83.04 रहा। 10वीं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81

और लड़कों का 72 फीसदी दर्ज किया गया। वहीं, 12वीं में छात्राओं का पासिंग प्रतिशत 86.4 और लड़कों का 78.8 फीसदी दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 छात्र-छात्राओं ने 99 प्रतिशत अंक लाकर पूरे राज्य में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। इनमें संध्या नायक, परीरानी प्रधान, और अशुल शर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं, दूसरी रैंक पर 5 छात्राओं ने 98.83 प्रतिशत के साथ अपनी जगह बनाई है, जिनमें रिया केशवानी, रानू सिद्धमयी साहू, रेणुका प्रधान, दीपांशी बौद्ध, और नंदिता देवदन के नाम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिज्ञासु वर्मा ने 98.6 प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर 98.2 प्रतिशत के साथ ओमनी, तीसरे रैंक पर 97.8 प्रतिशत के साथ कृष महंत, और चौथे स्थान पर 97.6 प्रतिशत के साथ 3 छात्र-छात्राओं ने टॉपर की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। चौथे स्थान पर रिया साहूस, शहनाज परवीन और ताहिर खान शामिल हैं।

2030-31 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य पर मंथन, पीयूष गोयल ने बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030-31 तक भारत के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना पर विचार करने और निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने वर्ष 2030-31 तक

कुल निर्यात का लक्ष्य 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखा है, जिसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात शामिल है। वाणिज्य विभाग ने एक सुव्यवस्थित निर्यात निगरानी फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो राष्ट्र के लक्ष्य को इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में बांटता है।

नई दिल्ली में भारत-इटली रक्षा वार्ता, इटली के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह

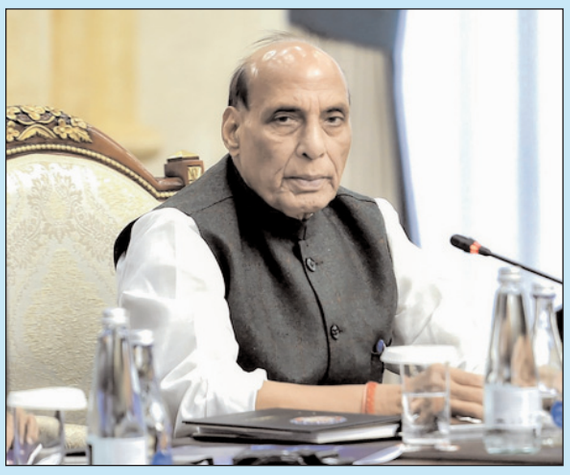

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेट्टो के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। यह द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य लगातार बदल रहा है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के चलते विभिन्न देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की अहमियत भी बढ़ गई है।

राजनाथ सिंह व इटली के रक्षामंत्री के बीच यह वार्ता 30 अप्रैल को नई दिल्ली में होगी। इसे भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

इसमें सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी, नई तकनीकों के आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा, ताकि दोनों देश एक साझा समझ विकसित कर सकें।

गौरतलब है कि भारत और इटली के बीच रक्षा संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है। अक्टूबर 2023 में राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के बाद इन संबंधों को नई गति मिली थी। उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब इटली के रक्षा मंत्री की यह पहली भारत यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों देश इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए गंभीर हैं। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए रक्षा और रणनीतिक साझेदारी समझौते ने भी इस रिश्ते को मजबूती दी है।

इस समझौते के बाद भारत और यूरोप के देशों के बीच रक्षा सहयोग के नए रास्ते खुले हैं, जिससे इटली के साथ साझेदारी को भी अतिरिक्त बल मिला है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस व चीन के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात व बातचीत की है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने इस बातचीत को बेहतरीन और सार्थक बताया।

माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर रक्षा सहयोग, सैन्य तकनीक और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में यह मुलाकात हुई। मंगलवार को ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन के बीच भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों देशों के रक्षामंत्रियों ने यहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा की।

महाराष्ट्र सरकार ने एआई नीति को दी मंजूरी, 1.5 लाख नौकरियों का लक्ष्य

मुंबई । महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में एआई नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे ले जाना है।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति को मंजूरी दे दी। इसे तकनीक के भविष्य की दिशा में राज्य का बड़ा कदम माना जा रहा है। मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक और एआई आधारित बदलाव उद्योगों और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रहे हैं। ऐसे समय में महाराष्ट्र नई तकनीक को अपनाकर और एआई की ताकत का उपयोग करके देश में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि यह एआई नीति महाराष्ट्र को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे ले जाएगी और रोजगार, उद्योग व नवाचार के नए अवसर पैदा करेगी।

सरकार के अनुसार, इस नीति का मुख्य लक्ष्य बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। इसके तहत करीब 1.5 लाख एआई आधारित नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लगभग 2 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भविष्य के लिए कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।

उद्योग और कारोबार में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 50 एआई टूल और उपयोग मॉडल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 'एप्लाइड एआई एक्सेलरेटर' पहल शुरू की जाएगी। इसके लिए मजबूत कंप्यूटिंग ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें राज्य में 2,000 जीपीयू उपलब्ध कराए जाएंगे।

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडः दोषी शरद कलस्कर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

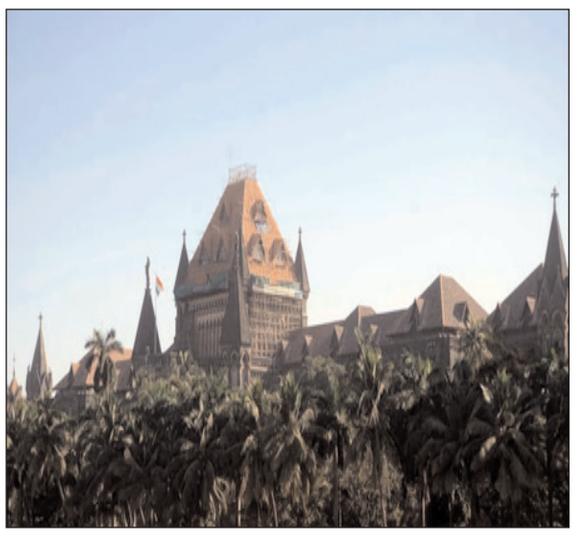

मुंबई । अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में दोषी शरद कलस्कर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई।

पुणे की विशेष न्यायालय ने साल 2024 में शरद कलस्कर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को कलस्कर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपील पर अंतिम फैसला आने तक जमानत देने की मांग कलस्कर की ओर से की गई थी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह भोसले की पीठ ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कलस्कर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जांच एजेंसी ने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर शरद की जमानत मंजूर कर ली।

20 अगस्त, 2013 को डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की पुणे के महर्षि विट्ठल रामजी ब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुणे की सत्र अदालत ने 2024 में अंदुरे और कलस्कर को दोषी ठहराते हुए डॉ. वीरेंद्र तावड़े, विक्रम भावे और वकील संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया था।

डॉ नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर ने इन तीनों की रिहाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसके अलावा, दाभोलकर परिवार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अंदुरे और कलस्कर को बरी किए जाने के फैसले को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मुक्ता का मानना है कि उनके पिता की हत्या सुनियोजित थी और इसमें एक बड़ी साजिश शामिल थी।

मुक्ता ने अपनी अपील में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर को खत्म करने की साजिश रची थी, जिन्होंने सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिति और अन्य समान संगठनों के खिलाफ अपने कड़े विचार व्यक्त किए थे। सत्र न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इस मामले में दोषी ठहराए गए और बरी किए गए तीनों आरोपी दक्षिणपंथी सनातन संस्था के सदस्य थे या उससे जुड़े हुए थे।

कलस्कर कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड में भी आरोपी हैं। यह मामला अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय की कोल्हापुर बेंच ने कलस्कर के साथ डॉ. वीरेंद्र सिंह तावड़े और अमोल काले को जमानत दे दी थी।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, पीआईबी फैक्ट-चेक यूनिट ने खारिज किया सोशल मीडिया पोस्ट का दावा

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दावा करने वाला आदेश फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।'

पीआईबी फैक्ट चेक ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया गया कि वे ऐसी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें और अपुष्ट दावों को साझा करने से बचें।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच नागरिकों की चिंताओं को शांत करने का प्रयास किया, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ा है।

यहां एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी, हालांकि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आवश्यक ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन भी दिया।

शर्मा ने कहा, 'एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए घबराएं नहीं।' उनके अनुसार, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ परिवहन में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की है।

सरकार का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया, जो एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, में अनिश्चितता के कारण वैश्विक तेल बाजार अस्थिर बने हुए हैं।

महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी के घर से बरामद किया आईएसआईएस से जुड़ा पत्र

मुंबई। महाराष्ट्र के मीरा रोड चाकू हमला मामले में जांच कर रही एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जांच के दौरान आरोपी जैब जुबेर अंसारी के घर से एक हस्तलिखित पत्र बरामद हुआ है, जिसमें उसने कट्टरपंथी विचारों और आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रति निष्ठा जताने की बात लिखी है।

एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, मीरा रोड के नया नगर इलाके में दो सिक्योरिटी गार्ड पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने अपने खिलाफ सबूत मिटाने की कोशिश की थी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने अपना एक मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था, ताकि जांच एजेंसियों के हाथ कोई अहम जानकारी न लग सके। अधिकारियों ने बताया कि उसने अपना दूसरा फोन कहीं फेंक दिया है, जिसकी तलाश जारी है।

जांच के दौरान उसके घर से मिला हस्तलिखित पत्र बेहद गंभीर और चिंताजनक माना जा रहा है। इस पत्र में आरोपी ने लिखा है कि उसने आईएसआईएस के प्रति 'बैअत' यानी निष्ठा ली है। इतना ही नहीं, उसने नोट पर आईएसआईएस का झंडा भी बनाया और कई उग्र बातें लिखीं।

पत्र में उसने लिखा, 'लोन वुल्फ तुम पर हमला करेंगे।' इसके साथ ही उसने यह भी लिखा कि अब से बिलाद अल-हिंद में तुम मुश्रिकीन असली जिहाद देखोगे। उसने आगे लिखा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह सभी मुसलमानों को राह दिखाए और युवाओं से कहते हैं कि वे अपने परिवार की चिंता किए बिना इस्लामिक स्टेट से जुड़ें। अल्लाह उन्हें एक दिन राह दिखाएगा। आज वे समझ नहीं रहे हैं।

आरोपी ने पत्र में खुद को और अपने जैसे लोगों को 'गुरबा' यानी अलग-थलग और ठुकराए गए लोग बताते हुए लिखा, 'आज हम अकेले हैं और सबने हमें ठुकरा दिया है, लेकिन हम गुरबा लोग हैं।' उसने यह भी लिखा कि परिवार, पत्नियां और माता-पिता तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह उन्हें राह दिखाए। पत्र के अंत में उसने लिखा, 'गाजा केवल खिलाफत से ही आजाद होगा। अल्लाह के बाद खिलाफत ही सुन्नियों की एकमात्र उम्मीद है।' ओटीएस के अनुसार, इस पत्र से आरोपी की मानसिकता और उसके संभावित आतंकी जुड़ाव के संकेत मिलते हैं। फिलहाल एजेंसी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी के नेटवर्क व संपर्कों का पता लगाने की कोशिश जारी है।

महाराष्ट्र में रिजल्ट के तुरंत बाद डिजीलॉकर पर मिलेगी डिग्री, मंत्री का निर्देश

मुंबई । महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और जरूरी सत्यापन पूरा होने के तुरंत बाद छात्रों की डिग्री प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर अपलोड किए जाएं। इसके लिए छात्रों को दीक्षांत समारोह तक इंतजार नहीं कराना पड़ेगा।

मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद कई छात्र विदेशों की यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने और दीक्षांत समारोह के बीच लंबे अंतर के कारण छात्रों को तय समय सीमा में डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने में दिक्कत होती है।

मंत्री ने कहा कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में देरी के कारण छात्रों को पढ़ाई या करियर के मौके नहीं गंवाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई छात्र सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर ले और उसका परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित हो जाए, सत्यापित डिग्री प्रमाणपत्र जल्द से जल्द डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।

चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी यूनिवर्सिटी डिजीलॉकर पर डिग्री प्रमाणपत्र अपलोड करने की एक समान प्रक्रिया अपनाएं।

उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा, ''इस फैसले से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी अवसरों, इंटर्नशिप और रोजगार के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

इंडिगो की बड़ी घोषणाः 1 मई से फिर से शुरू होंगी कतर के लिए उड़ान सेवाएं

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 1 मई 2026 से कतर की राजधानी दोहा के लिए अपनी सभी फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और एयरस्पेस बंद होने के कारण इन उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। अब हालात सामान्य होने के बाद एयरलाइन ने दोबारा संचालन शुरू करने का फैसला लिया है।

एक नोट में कंपनी ने बताया कि इंडिगो अब भारत के सात प्रमुख शहरों—बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कन्नूर, कोच्चि और मुंबई—से दोहा के लिए अपनी नियमित उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन हर हफ्ते 60 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जिससे यात्रियों को पहले की तरह आसान और किफायती यात्रा सुविधा मिल सकेगी।

दोहा भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब है। इंडिगो की सेवाएं दोबारा शुरू होने से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कतर से भारत आने वाले यात्रियों को भी इंडिगो के बड़े नेटवर्क के जरिए देश के कई शहरों और अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचने में आसानी होगी।

एयरलाइन ने कहा है कि सभी उड़ानें मौजूदा एयरस्पेस स्थितियों और संबंधित अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएंगी। इंडिगो ने यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई है।

यात्री अपनी टिकट इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स के जरिए आसानी से बुक कर सकते हैं। एयरलाइन का कहना है कि वह किफायती किराए और समय पर उड़ानों के साथ यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में इंडिगो भारत की सबसे पसंदीदा एयरलाइनों में से एक है और दुनिया की तेजी से बढ़ती एयरलाइनों में शामिल है। 400 से ज्यादा विमानों के बेड़े के साथ यह रोजाना 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है और 95 से ज्यादा घरेलू व 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है।

इंडिगो को 2025 में स्काईट्रैक्स द्वारा 'भारत और दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन' का खिताब भी मिल चुका है, जबकि एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम ने इसे एशिया-पैसिफिक की सबसे समयनिष्ठ एयरलाइनों में शामिल किया है।

'छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026' को मंजूरी

रायपुर। नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिपरिषद ने ''छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026'' को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा।

साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा, दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रिपरिषद द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने तथा विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज एवं मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए, उस निर्णय के पालन में जारी समस्त आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण और गणना अभियान

मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह, पहली बार पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल माध्यम से संचालित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से शुरू होकर 30 मई 2026 तक चलेगा। इस अभियान के दौरान राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक मकान, परिवार और आवासीय संरचना से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रशासन ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

बुधवार को जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान की कार्ययोजना, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं और निगरानी तंत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गणना कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस बार मकान सूचीकरण और जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रगणकों को मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए जानकारी दर्ज करनी होगी। फील्ड से प्राप्त आंकड़े सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड होंगे, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कार्य की निगरानी भी आसान होगी।

बैठक में जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण समय पर पूरा कराया जाए। उन्हें केवल डेटा भरने की तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि फील्ड में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि घर बंद मिलने, जानकारी देने में संकोच या अन्य परिस्थितियों में भी कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाए।

जनगणना कार्य में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले कर्मचारियों को ही जानकारी उपलब्ध कराएं।

लू के थपेड़ों से बचाव के लिये एनएचएआई ने जारी किये कर्मियों के लिए दिशा-निर्देश

रायपुर। वर्तमान ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू की स्थिति और सामान्य से अधिक तापमान को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कार्यबल के स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों को अनिवार्य करने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र के तहत निर्माण स्थलों, रखरखाव कार्यों और टोल प्लाजा के लिए अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को रेखांकित करते हैं। सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित इन सुरक्षा उपायों को सभी ठेकेदारों, रियायतग्राहियों और टोल संग्रह एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों और श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत लागू किया जाएगा।

निर्माण एवं रखरखाव परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश

एनएचएआई ने ठेकेदारों और रियायतग्राहियों को निर्देश दिया है कि वे श्रमिकों के लिए अलग-अलग कार्य घंटे निर्धारित करें, ताकि दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच के भीषण गर्मी के समय से बचा जा सके। डामर बिछाने, वेल्डिंग आदि जैसे श्रम-प्रधान और गर्मी पैदा करने वाले कार्य सुबह जल्दी या देर शाम के समय किए जाने चाहिए। नियमित अंतराल पर अनिवार्य 'कूलिंग ब्रेक' निर्धारित किए गए हैं और जिनकी आवृत्ति अत्यधिक गर्मी के अलर्ट के दौरान बढ़ाई जाएगी।

श्रमिकों के अनुकूल पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि नए या वापस लौटने वाले कर्मचारियों को 3-5 दिनों की अवधि में धीरे-धीरे कठिन कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। श्रमिकों को लू से संबंधित बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे हीटस्ट्रोक, की पहचान और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

स्थल पर पर्याप्त सुविधाओं के लिए अस्थायी छायादार विश्राम क्षेत्र, उचित वेंटिलेशन के साथ, तथा ठंडे और स्वच्छ पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिक उपचार केंद्र, गश्ती वाहन और साइट पर्यवेक्षकों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) और ग्लूकोज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया प्रदर्शन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में उचित स्थान दिलाने की मांग अब तेज हो गई है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने स्व-जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने को लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने बुधवार को दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जारी स्व-जनगणना पोर्टल में मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है, उन्होंने कहा कि नेपाली जैसी विदेशी भाषा और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख पोर्टल में मौजूद है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजभाषा आयोग के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसके बावजूद जनगणना जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में छत्तीसगढ़ी भाषा को नजरअंदाज करना साढ़े तीन करोड़ छत्तीसगढ़ी भाषीयों के साथ अन्याय है।

तकनीक आधारित 'प्रचार ऐप' से होगी आउटडोर मीडिया मॉनिटरिंग

- अब हर होर्डिंग पर रहेगी रीयल-टाइम नजर
- प्रिंटिंग पॉलिसी पर किया जा रहा है अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन

रायपुर। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और नई पहलों के प्रचार-प्रसार में आउटडोर मीडिया एक अत्यंत प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित है। इसमें होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, ब्रांडिंग, डिजिटल वॉल पेंटिंग्स और एलईडी वैन अभियान शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, बस स्टॉप्स तथा प्रमुख यातायात मार्गों जैसे उच्च आवागमन वाले स्थानों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से अधिक होता है।

आउटडोर मीडिया के क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग एक बड़ी चुनौती रही है। कई मामलों में यह शिकायतें सामने आई हैं कि वेंडर्स द्वारा सरकारी विज्ञापनों की स्थापना में देरी की गई या निगरानी के अभाव में उन्हें समय से पहले हटाकर उनकी जगह व्यावसायिक विज्ञापन लगा दिए गए।

इस समस्या के समाधान के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम 'प्रचार ऐप' विकसित किया गया है। यह प्रणाली तीन चरणों में कार्य करती है। पहले चरण में विभाग प्रचार अभियान की योजना बनाती है, पैनल में शामिल एजेंसियों और उनके एसेट्स का चयन कर प्रचार अभियान कार्य आवंटित करती है। दूसरे चरण में वेंडर्स प्रचार अभियान की समीक्षा कर क्रियान्वयन की योजना बनाती है और एसेट्स को माउंटर्स को सौंपती है। तीसरे चरण में माउंटर्स मैदानी स्तर पर निर्धारित स्थानों पर क्रिएटिव सामग्री स्थापित करती है।

तालाब में डूबने से जुड़वां बहनों की मौत

सक्ती। जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र अंतर्गत लवसरा गांव में दो जुड़वाँ के तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

मृतक की पहचान दीप्ती गोंड (6 वर्ष) और दिव्या गोंड (6 वर्ष) के रूप में हुई है।

दोनों बच्चियां सुबह करीब 9:30 बजे अपने घर के पास खेल रही थीं। वे दोनों तालाब में गिर गए और गहरे पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद गांव के लोगों ने तालाब में दोनों के शव तैरते हुए देखे, जिसके बाद वे उग्र होकर बाहर चले गए।

बिना देर किए दोनों बहनों के शवों को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती के लिए भेजा गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पुलिस की ओर से मास्क और पेस्ट को लेकर भेजा गया है। यह घटना लवसेरा गांव में गहरे शोक की स्थिति बनी हुई है।

दुर्ग का जेंडर-बैलेंस्ड सिस्टम बना रोल मॉडल टूटते परिवारों को जोड़ने की नई पहल

रायपुर। तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है। दुर्ग जिले में शुरू हुई जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था आज पारिवारिक विवाद समाधान का एक ऐसा समावेशी मॉडल बनकर उभरी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है।

सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले मुख्यत: महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच बन चुका है। यहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जा रहा है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुआ यह केंद्र समय के साथ अपने दायरे का विस्तार करता गया। बदलते पारिवारिक समीकरणों और विवादों के नए स्वरूप को देखते हुए इसमें जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग को लागू किया गया, जिससे हर पक्ष को निष्पक्ष और संतुलित सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है—पुरुष काउंसलर की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव से जूझते हुए परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को समझने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की मांग बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। वहीं दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, संवाद और परामर्श की प्रक्रिया पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो रही है।

महिला प्रधान आरक्षक ने थाने में महिला से की मारपीट, पीड़िता ने एसपी से की शिकायत

दुर्ग। जिले में लेडी हेड कॉन्स्टेबल ने महिला को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बाल खींचकर जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि हेड कॉन्स्टेबल ने महिला की मां को भी लात मारी। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ज्वेलरी शॉप में पैसे के लेन-देन से जुड़ा है।

घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का नाम जया गाड़े है, जो कि एडवांस में दिए पैसे लेने सहेली ज्वेलर्स पहुंची थी। आरोप है कि संचालक ने पैसे देने इनकार करते हुए पुलिस को बुला ली। इसके बाद संचालक और महिला में विवाद हो गया। इस दौरान महिला और कॉन्स्टेबल के बीच भी हाथापाई हो गई।

पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। यह भी आरोप है कि पुसिस ने उसके साथ थाने के अंदर पर भी मारपीट की। इस पूरे मामले में पीड़िता ने एसएसपी विजय अग्रवाल से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जया गाड़े ने 15 अप्रैल को सहेली ज्वेलर्स में गहने बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था। 19 अप्रैल करीब 4.30 बजे वह अपने मां के साथ ज्वेलरी शॉप पहुंची और उसने किसी कारण वश ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। इसके जया ने एडवांस के तौर पर दिए 50 हजार रुपए वापस मांगे। आरोप है कि संचालक ने पैसे से इनकार करते हुए पुलिस बुला ली। इस दौरान महिला और स्टाफ के बीच जमकर विवाद हुआ। पीड़िता का आरोप है कि महिला हेड कांस्टेबल लता सुमन साहू ने हालात समझने की कोशिश तक नहीं की और गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

अचल संपत्ति की रजिस्ट्री हुई सस्ती, 0.60% उपकर समाप्त-आम जनता को बड़ी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय प्रदेश में सुशासन और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत अब अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों के पंजीयन पर बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को सरल और किफायती बनाना है। ऐसे में यह निर्णय पूरी तरह जनहित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के आम नागरिकों, किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों तथा संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब संपत्ति पंजीयन की लागत कम होगी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुलभ, सरल और किफायती बनेगी।

पंजीयन मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उपकर समाप्त करने की पहल की गई थी, जिसके अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया।

युवा फेस्ट 2026 का सकारात्मक असर: छात्र प्रतीक ताम्रकार का आईटी कंपनी में चयन

रायपुर। धमतरी में 24-25 अप्रैल को आयोजित युवा फेस्ट 2026 के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। यह आयोजन युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हो रहा है। इसी क्रम में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप से एक प्रेरणादायक सफलता कहानी सामने आई है।

अभनपुर निवासी कक्षा 12वीं के छात्र प्रतीक ताम्रकार का चयन बेंगलुरु स्थित टेक्नोज साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड में समर इंटर्नशिप हेतु किया गया है। यह अवसर उन्हें युवा फेस्ट के दौरान आयोजित एआई वर्कशॉप में सक्रिय सहभागिता, तकनीकी समझ और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त हुआ है। वे आगामी दो माह (अप्रैल से जून 2026) तक कंपनी के साथ कार्य करते हुए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बेंगलुरु से आई विशेषज्ञ टीम द्वारा युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं आधुनिक तकनीकों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। वर्कशॉप में प्रतिभागियों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट आधारित सीखने और करियर मार्गदर्शन का भी अवसर मिला। प्रतीक ने अपनी जिज्ञासा, नवाचार की सोच और सीखने की प्रतिबद्धता से प्रशिक्षकों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें यह महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने प्रतीक ताम्रकार को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि युवा फेस्ट का उद्देश्य केवल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं की प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा और मंच उपलब्ध कराना है। प्रतीक की सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर ग्रामीण एवं छोटे शहरों के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। कलेक्टर ने जिले के अन्य युवाओं से भी इस प्रकार के नवाचार एवं कौशल आधारित कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की, ताकि वे आधुनिक तकनीकों से जुड़कर अपने करियर को नई दिशा दे सकें।

समग्र रूप से 'युवा फेस्ट-2026' केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। इसने शिक्षा, संस्कृति, खेल और तकनीक के समन्वय के माध्यम से युवाओं को आत्मविश्वास, नवाचार और नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

भारत-श्रीलंका नौसेना का संयुक्त 'डाइवेक्स' अभ्यास संपन्न, गहरे समुद्र में रेस्क्यू क्षमता हुई मजबूत

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की नौसेना ने संयुक्त डाइविंग अभ्यास को अंजाम दिया है। यह यह इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स अभ्यास का चौथा संस्करण था। भारतीय नौसेना ने बताया कि यह अभ्यास 21 से 28 अप्रैल के बीच कोलंबो में संपन्न हुआ।

इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का विशेष जहाज आईएनएस निरीक्षक शामिल हुआ, जो गहरे समुद्र में डाइविंग और पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ दोनों देशों की डाइविंग टीमों ने मिलकर काम किया, जिससे आपसी तालमेल और पेशेवर समझ और मजबूत हुई।

यह अभ्यास खास तौर पर पानी के अंदर होने वाले जटिल ऑपरेशन पर केंद्रित था। इसमें गहरे समुद्र में उन्नत डाइविंग अभ्यास, मिक्स्ड गैस डाइविंग जैसी तकनीकी ट्रेनिंग व बंदरगाह और खुले समुद्र दोनों जगह डाइव का अभ्यास किया गया। सबसे खास बात यह रही कि नौसैनिक डाइवर्स ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के जहाजों के मलबे एसएस वूस्टर और एसएस पर्सियस के नजदीक जाकर यह अभ्यास किया। सप्ताह भर चले इस अभ्यास में भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के गोताखोर दलों ने मिलकर कई तरह के विशेष डाइविंग ऑपरेशन और प्रशिक्षण गतिविधियां को अंजाम दिया। इनमें गहरे समुद्र में बचाव कार्य, तकनीकी डाइविंग, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देना शामिल है।

दोनों देशों के डाइवर्स ने 55 मीटर से ज्यादा गहराई तक सफल डाइव लगाई। नौसेना के मुताबिक यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे भविष्य में सर्च, रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन में उनकी संयुक्त क्षमता और मजबूत होगी।

इस अभ्यास के दौरान श्रीलंकाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी एस जे कुमारा ने आईएनएस निरीक्षक का दौरा किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के सहयोग और ट्रेनिंग की सराहना की।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से दोनों देशों को एक-दूसरे से सीखने का अच्छा मौका मिलता है। इसके अलावा पनडुब्बी से जुड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी अहम गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाएगा। इन अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना था।

तेलंगाना: 10वीं की परीक्षा में लड़कियों ने फिर दिखाया दम, 96.26 प्रतिशत के साथ लड़कों से रहीं आगे

हैदराबाद। तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई तेलंगाना) ने बुधवार को माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी)-कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया।

घोषित नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष रेगुलर उम्मीदवारों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.15 रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहतर है। पिछले साल 10वीं की परीक्षा में 92.78 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए थे।

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (बीएसई) के अनुसार, मार्च-अप्रैल में आयोजित हुई परीक्षाओं में कुल 5,16,815 रेगुलर छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 4,91,774 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

रेगुलर लड़कों का पासिंग प्रतिशत 94.07 है, जबकि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.26 दर्ज किया गया है। पिछले साल रेगुलर लड़कों का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.32 था, जबकि लड़कियों का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.26 था। सरकार के सलाहकार डॉ. के केशवा राव ने बुधवार को शिक्षा सचिव योगिता राणा और स्कूल शिक्षा निदेशक ई नवीन निकोलस की मौजूदगी में नतीजे जारी किए। जिलों में, मुलुगु 99.30 फीसदी पास प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर रहा। नागरकुरनूल दूसरे और निर्मल तीसरे स्थान पर रहा, जिनका पास प्रतिशत 99.03 और 98.96 रहा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, दानसारी सीतक्का ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजों में मुलुगु जिले के पहले स्थान पर आने पर खुशी जाहिर की।

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी, 2 मई के बाद मौसम में बदलाव की संभावना

भोपाल। भोपाल स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और संभावित वायुमंडलीय गड़बड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कई क्षेत्रों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खजुराहो में राज्य का अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

विदिशा, रायसेन, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, दमोह और सागर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है।

दिन की भीषण गर्मी के अलावा, उमरिया जिले में रातें भी गर्म हैं, जहां न्यूनतम तापमान असहनीय रूप से अधिक बना हुआ है। पचमढ़ी में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे मौजूदा गर्मी से कुछ राहत मिली।

भोपाल में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों ने कई मौसमी प्रणालियों की पहचान की है, जिनमें उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ और पंजाब और राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण शामिल हैं।

इन प्रणालियों के कारण राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।

ग्वालियर, दतिया, भिंड, मोरेना, सिंगरौली, रीवा और पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों के आसपास के जिले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं।

भोपाल में आसमान मुख्यत: साफ रहने की संभावना है, और हवा की औसत गति 14 से 16 किमी प्रति घंटा रहेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र ने निवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सीधी धूप से बचने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है।

किसानों को फसलों की नियमित सिंचाई सुनिश्चित करने और पशुओं को छायादार, हवादार आश्रयों में रखने की सलाह दी गई है। आगे की बात करें तो विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसके बाद लगभग 2 मई को क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से तापमान में फिर से वृद्धि होगी।

तीव्र सौर विकिरण और तेज हवाओं (सीहोर में 52 किमी प्रति घंटा और भोपाल में 43 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई) के संयोजन से सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मिट्टी में नमी की कमी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।

जुबीन गर्ग मौत मामला: कोर्ट ने आरोपी मैनेजर से जुड़े खातों को फ्रीज करने का दिया आदेश

गुवाहाटी। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिवंगत गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा से जुड़े कुछ लोगों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। शर्मा इस मामले में कथित भूमिका को लेकर फिलहाल जेल में बंद है।

अदालत ने इसके साथ ही महाबीर एक्वा नामक संस्था को भी जब्त करने का निर्देश दिया है, जिसे शर्मा से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत के इस फैसले को मामले की सुनवाई में अहम कदम माना जा रहा है।

यह मामला जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा है, जिनका निधन पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास तैराकी के दौरान हुआ था। घटना से एक दिन बाद उन्हें एनईआईएफ बैनर के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देनी थी।

घटना के बाद असम पुलिस की सीआईडी द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विस्तृत जांच की और दिसंबर में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सात लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें महंता का नाम भी शामिल है। इनमें से चार आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान इस मामले को 'सीधी और साफ हत्या' करार दिया था, जिससे सरकार का रुख साफ हो गया था।

हालांकि, दूसरी ओर सिंगापुर पुलिस की समानांतर जांच में किसी भी तरह की साजिश या हत्या के सबूत नहीं मिलने की बात कही गई थी। इसके बावजूद असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी एजेंसियों की जांच का असर राज्य में चल रही जांच और मुकदमे पर नहीं पड़ेगा।

मामले की अगली सुनवाई और जमानत याचिका पर फैसला अब काफी अहम माना जा रहा है।

मिजोरम: नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हेरोइन बरामद

आइजोल। मिजोरम पुलिस ने राज्यभर में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस कार्रवाई के दौरान तीन करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सभी लोग सीमा पार से जुड़े तस्करी में संलिप्त बताए जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, सबसे पहली कार्रवाई 26 अप्रैल को की गई थी। तब 95.8 लाख की कीमत वाली 480 ग्राम हेरोइन बरामद की थी और असम के सुल्तान अहमद लस्कर (35) को भी गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई में अब्दुल सोलम बरभुइया (27) को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इसके पास से 69.2 लाख रुपए की कीमत वाली 479 ग्राम हेरोइन जब्त की थी। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले 24 अप्रैल को पुलिस ने 61.6 लाख रुपए की कीमत वाली 308 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने थांगरोखावली (42) को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए इन सभी लोगों में मुख्य रूप से म्यांमार से जुड़ा एक सप्लायर और आइजोल में हेरोइन लेने वाला एक स्थानीय व्यक्ति शामिल था। उसी दिन पुलिस ने 4.4 लाख की कीमत वाली 22 ग्राम हेरोइन जब्त की थी और दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। उधर, 24 अप्रैल को पुलिस ने नगोपा में 70.2 लाख की कीमत वाली 351 ग्राम हेरोइन और 21 अप्रैल को आइजोल में बरामद की थी।

पाकिस्तान में गरीब परिवारों के बच्चों के सामने शिक्षा में बड़ी बाधाएं, लाखों अब भी स्कूल से बाहर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को अब भी शिक्षा हासिल करने में गंभीर संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संपन्न परिवारों के बच्चों को बेहतर स्कूलिंग और उज्ज्वल करियर के अवसर मिल रहे हैं। यह खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 2.62 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 1.34 करोड़ लड़कियां शामिल हैं। स्कूल जाने की उम्र के लगभग 20 से 28 प्रतिशत बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं। इनमें से कई बच्चों को शिक्षा के बजाय जीविका को प्राथमिकता देनी पड़ती है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित संपादकीय में सवाल उठाया गया कि कुछ बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, जबकि अन्य इससे वंचित क्यों रह जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्कूल केवल उन लोगों के लिए क्यों हैं, जो उनका खर्च उठा सकते हैं, जबकि लाखों बच्चों को कमजोर विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है।

संपादकीय में कहा गया कि बच्चे जन्म से समान होते हैं और उनमें वर्ग, हैसियत या भेदभाव की कोई भावना नहीं होती। समाज ही उन्हें असमानता और ऊंच-नीच का एहसास कराता है। रिपोर्ट में बताया गया कि खासतौर पर ग्रामीण और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों के लाखों बच्चों को बुनियादी अधिकार भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी के अवसरों तक सीमित पहुंच मिलती है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सहायक प्रोफेसर मुजीब अली ने कहा कि वर्षों बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। संपन्न परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे वे प्रतिष्ठित करियर तक पहुंचते हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के कार्यकाल में हुए 397 करोड़ के टेंडर घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तमिलनाडु के विद्युत और निषेध एवं उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में सेंथिल बालाजी के 2021 से 2023 के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मर टेंडर खरीद में कथित 397 करोड़ रुपए की अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि जांच का नेतृत्व करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। पीठ ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर सीबीआई द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया और एक स्वतंत्र एवं व्यापक जांच की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और डीवीएसी को केंद्रीय एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज शीघ्रता से सौंप दिए जाएं। अदालत ने सीबीआई को प्रभावी जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।

आईपीएल में निडरता से खेल रही युवा पीढ़ी, यह भारतीय क्रिकेट में रोमांचक दौर की शुरुआत है: इरफान पठान

मुंबई। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि आज के दौर की युवा पीढ़ी जिस निडर अंदाज में खेल रही है, उससे भारतीय क्रिकेट में एक रोमांचक दौर की शुरुआत हो रही है। पठान के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं।

इरफान पठान ने ईयूटी20 बेल्जियम की जर्सी लॉन्च के मौके पर 'आईएएनएस' से कहा, 'यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय है। जिस तरह ये खिलाड़ी निडरता से खेलते हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। उन्हें आउट होने का कोई डर नहीं होता। उन्हें इस बात की भी कोई चिंता नहीं होती कि उनके सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है। एक 15 साल का लड़का (सूर्यवंशी) जाता है और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक को जोरदार शॉट मारता है। इस समय क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम से बेहतर कोई दूसरी टीम नहीं है।'

पठान ने आगामी ईयूटी20 बेल्जियम टूर्नामेंट में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की, जहां वह 'जेंट ग्लेडिएटर्स' टीम के सह-मालिक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेल्जियम क्रिकेट फेडरेशन के साथ मिलकर आयोजित की जा रही इस लीग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी, जो बेल्जियम के अलग-अलग बड़े शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह टूर्नामेंट 6 से 14 जून तक ब्रसेल्स के हॉफस्टेड में स्थित '12 स्टार्स क्रिकेट क्लब' में खेला जाएगा। इस लीग के पहले सीजन में लीज रेड लायंस, जेंट ग्लेडिएटर्स, एंटवर्प एंकर्स, जेबी ब्रुग्स और एक्सेल यूनाइटेड ब्रुसेल्स शामिल होंगी।

उद्धव ठाकरे के चुनाव से हटने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी

मुंबई। शिवसेना यूबीटी द्वारा 12 मई को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित करने के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में दरारें उभर आई हैं।

कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी, खासकर तब जब शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 13 मई को उच्च सदन में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव से हटने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने घोषणा की है कि पार्टी राज्य विधानसभा परिषद चुनावों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी द्वारा उद्धव ठाकरे के बजाय अंबादास दानवे को उम्मीदवार बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पिछले सप्ताह सपकाल और राज्य कांग्रेस विधानसभा दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने घोषणा की थी कि पार्टी राज्य विधान परिषद चुनावों में उद्धव ठाकरे का समर्थन करेगी और अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि, दोनों ने संकेत दिया था कि यदि उद्धव ठाकरे चुनाव न लड़ने का फैसला करते हैं, तो कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी।

नौ सीटों के चुनाव के लिए कोटा 29 वोट है। वर्तमान में एमवीए की संख्या 46 है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के 20, कांग्रेस के 16 और एनसीपी (एसपी) के 10 सदस्य शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है।

पिछले सप्ताह सपकाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। सपकाल ने उद्धव ठाकरे को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन का प्रमुख चेहरा बताते हुए उनका पुरजोर समर्थन किया और कहा कि गठबंधन उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा।

संपादकीय

राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण और न्याय की चुनौतियां

महेन्द्र तिवारी

राजा रघुवंशी का प्रकरण आधुनिक समय की उन सबसे हृदयविदारक घटनाओं में से एक है जिसने भारतीय समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह मात्र एक आपराधिक घटना नहीं है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, अटूट विश्वास और विश्वासघात की पराकाष्ठा का एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी न्याय प्रणाली की सूक्ष्मताओं को भी कटघरे में खड़ा करता है। वर्ष 2025 में आरंभ हुई यह दुखद कथा 2026 में भी जनमानस के बीच गहन विमर्श का केंद्र बनी हुई है, विशेषकर उस समय जब इस संपूर्ण प्रकरण की मुख्य अभियुक्त को न्यायालय से सशर्त मुक्ति प्राप्त हुई है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि कभी-कभी वास्तविकता किसी भी काल्पनिक कथा से अधिक भयावह और विचलित करने वाली हो सकती है। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जड़ें इंदौर के एक सामान्य परिवार से जुड़ी हैं। इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी का विवाह 11 मई 2025 को सोनम के साथ अत्यंत हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ था। परिवार के सदस्यों और मित्रों के अनुसार यह एक अत्यंत सुखी और सामान्य विवाह प्रतीत होता था, जिसमें किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। विवाह के पश्चात के रीति-रिवाजों को पूर्ण करने के बाद, अपनी नई जीवन यात्रा को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से यह दंपति 20 मई 2025 के आसपास मेघालय की प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने के लिए प्रस्थान कर गया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि खुशियों की यह खोज एक भयानक त्रासदी में परिवर्तित होने वाली है। मेघालय की वादियों में भ्रमण के दौरान 23 मई 2025 वह अंतिम तिथि थी जब राजा और सोनम को अंतिम बार एक साथ देखा गया था। इसके पश्चात अचानक उनका अपने परिवार से संपर्क विच्छेद हो गया। कई घंटों तक कोई सूचना न मिलने और संचार के सभी साधन बंद होने के कारण परिवार की चिंता बढ़ती गई। अंततः स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इस संदर्भ में सूचित किया गया। इसके पश्चात एक व्यापक खोज अभियान का सूत्रपात हुआ जिसमें स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ आपदा प्रबंधन दल और अन्य जांच एजेंसियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कई दिनों की निरंतर खोज और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात 2 जून 2025 को राजा का निष्प्राण शरीर एक अत्यंत गहरी खाई से बरामद किया गया। इस समाचार ने न केवल रघुवंशी परिवार को अपूर्णीय क्षति पहुँचाई बल्कि संपूर्ण देश में सनसनी फैला दी।

प्रारंभिक स्तर पर यह मामला एक रहस्यमय दुर्घटना प्रतीत हो रहा था क्योंकि राजा की पत्नी सोनम उस स्थान से लापता थी। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली और विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। अंततः 8 जून 2025 को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बंदी बना लिया गया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इस घटना के पीछे छिपे काले सत्यों की परतें खुलने लगीं। जांच अधिकारियों ने उद्भेदन किया कि राजा की मृत्यु कोई संयोग या दुर्घटना नहीं थी, अपितु यह एक अत्यंत सुव्यवस्थित और क्रूर षड्यंत्र का परिणाम थी। पुलिस के दावों के अनुसार, सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध की रूपरेखा तैयार की थी।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि हत्या की इस वारदात को मेघालय के सोहरा क्षेत्र के अत्यंत दुर्गम और एकांत स्थान पर अंजाम दिया गया था। वहां अपराधी पूर्व से ही घात लगाकर बैठे थे। आरोप है कि सोनम सुनियोजित तरीके से राजा को उस एकांत स्थान पर ले गई, जहां पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हमलावरों ने उस पर प्रहार किया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शरीर को खाई में फेंक दिया। यह विवरण किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि यह उस पवित्र बंधन के विरुद्ध था जिसमें दो व्यक्ति एक-दूसरे की सुरक्षा का वचन लेते हैं।

आरक्षी विभाग ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए साक्ष्यों का संकलन किया और सितंबर 2025 में न्यायालय के समक्ष लगभग 790 पृष्ठों का एक विशाल आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में सोनम, राज कुशवाहा और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध वैज्ञानिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया गया था। इस आरोप पत्र की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह मामला कानूनी रूप से अत्यंत सुदृढ़ है। इस अवधि के दौरान अभियुक्तों की ओर से कई बार जमानत के लिए आवेदन किया गया, परंतु अपराध की प्रकृति और साक्ष्यों की प्रबलता को देखते हुए आरंभिक 3 प्रयासों में सोनम को कोई राहत नहीं मिली। वह लगभग 10 महीनों तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल की सलाखों के पीछे रही।

वर्ष 2026 के अप्रैल माह में इस प्रकरण ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। शिलांग की एक अदालत ने सोनम की जमानत याचिका पर विचार करते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में जांच प्रक्रिया में व्याप्त कुछ गंभीर विसंगतियों और तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाया। न्यायालय का यह प्रेक्षण था कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके अधिकारों और आरोपों की जानकारी उस प्रकार नहीं दी गई जैसा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अनिवार्य है।

उच्च शिक्षा में 'मार्केट फॉर लेमन्स'

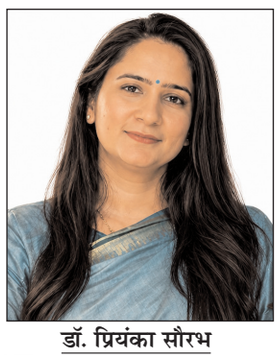

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आया है। एक ओर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे समय में अर्थशास्त्री जॉर्ज अकेलॉफ का 'मार्केट फॉर लेमन्स' सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता की सही जानकारी नहीं होती, तब निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार पर हावी हो जाते हैं और अच्छे उत्पाद पीछे हट जाते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी उपभोक्ता हैं और संस्थान सेवा प्रदाता। जब विद्यार्थियों को संस्थानों की वास्तविक स्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, रोजगार संभावनाओं, शोध कार्य और आधारभूत सुविधाओं की सही जानकारी नहीं मिलती, तब वे कमज़ोर संस्थानों में प्रवेश लेने को विवश हो जाते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार मुख्य रूप से नीतिगत प्रयासों के कारण हुआ है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने, ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया। इससे शिक्षा तक पहुँच बढ़ी और अधिक विद्यार्थियों को अवसर मिला, परंतु संस्थानों की गुणवत्ता उसी गति से विकसित नहीं हो सकी। अनेक निजी संस्थान आकर्षक विज्ञापन, भव्य परिसर और बड़े-बड़े दावे करके विद्यार्थियों को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि वास्तविकता में वहाँ योग्य शिक्षक, शोध वातावरण और रोजगारपरक शिक्षा का अभाव होता है। सरकारी आँकड़े भी अक्सर विलंब से आते हैं या सामान्य लोगों की समझ से परे जटिल रूप में उपलब्ध होते हैं। परिणामस्वरूप विद्यार्थी और अभिभावक सही निर्णय नहीं ले पाते। यही स्थिति निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षा बाजार को जन्म देती है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ की। इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन निश्चित मानकों के आधार पर करना है। इसमें शिक्षण व्यवस्था, संसाधन, शोध कार्य, स्नातक परिणाम, समावेशन और प्रतिष्ठा जैसे पहलुओं को देखा जाता है। इस व्यवस्था ने पहली बार विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच दिया जहाँ वे विभिन्न संस्थानों की तुलनात्मक स्थिति जान सकते हैं। इससे संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अनेक महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों की नियुक्ति, शोध प्रकाशनों, रोजगार सहायता केंद्रों और आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना प्रारंभ किया।

इस रैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के संकेत उपलब्ध कराए। अब विद्यार्थी केवल विज्ञापनों या प्रचार सामग्री पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि संस्थान की स्थिति, शोध प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम और समावेशन जैसी जानकारियों को देखकर निर्णय ले सकते हैं। इससे सूचना के अभाव की समस्या में कुछ कमी आई है। सरकार के लिए भी यह एक महत्त्वपूर्ण नीति उपकरण सिद्ध हुआ है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन संभव हुआ है।

फिर भी यह व्यवस्था पूर्ण समाधान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह काफी हद तक संस्थानों द्वारा स्वयं दिए गए आँकड़ों पर आधारित रहती है। यदि कोई संस्थान गलत या बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी दे, तो रैंकिंग की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। दूसरा, शोध कार्य को अधिक महत्व मिलने से वे महाविद्यालय पीछे रह जाते हैं जो मुख्य रूप से शिक्षण पर केंद्रित हैं।

तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों या नवस्थापित संस्थानों के लिए बड़े और पुराने शहरी संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। चौथा, रैंकिंग वर्ष में एक बार आती है, जबकि विद्यार्थियों को कई बार वास्तविक समय की जानकारी की आवश्यकता होती है। पाँचवाँ, देश के विशाल उच्च शिक्षा ढाँचे की तुलना में सीमित संस्थान ही प्रमुखता से सामने आते हैं, जिससे अनेक संस्थान पारदर्शी मूल्यांकन से बाहर रह जाते हैं।

विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए ऐसे मॉडल अपनाए जाते हैं जिनमें पूर्व छात्रों की संतुष्टि, अंतरराष्ट्रीय पहचान, नियोक्ताओं की राय, शोध प्रभाव और वैश्विक सहयोग जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जाता है। भारत भी अपनी व्यवस्था को अधिक व्यापक और बहुआयामी बनाकर इन अनुभवों से सीख सकता है।

विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, संस्थानों द्वारा दिए गए आँकड़ों का स्वतंत्र एजेंसियों से सत्यापन कराया जाए, ताकि गलत जानकारी देने की प्रवृत्ति समाप्त हो। दूसरा, शिक्षण गुणवत्ता, छात्र-शिक्षक अनुपात, रोजगार उपलब्धता और शुल्क के मुकाबले लाभ को अधिक महत्व दिया जाए। तीसरा, केवल क्रम संख्या देने के स्थान पर समूह आधारित श्रेणी व्यवस्था अपनाई जाए, जिससे छोटे और उभरते संस्थानों को भी सम्मानजनक स्थान मिल सके। चौथा, एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच विकसित किया जाए जहाँ प्रत्येक संस्थान की अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो। पाँचवाँ, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर भी रैंकिंग तैयार की जाए, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को अपने आसपास बेहतर विकल्प मिल सकें। छठा, विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।

अंततः उच्च शिक्षा केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, विश्वास और समान अवसर का प्रश्न है। यदि पारदर्शिता का अभाव रहेगा तो विद्यार्थी निम्न स्तर के संस्थानों के जाल में फँसते रहेंगे और उनका भविष्य प्रभावित होगा। राष्ट्रीय रैंकिंग व्यवस्था ने सकारात्मक शुरुआत अवश्य की है, किंतु इसे अधिक स्वतंत्र, विश्वसनीय और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है। जब सही जानकारी, प्रभावी नियमन और गुणवत्तापूर्ण संस्थान एक साथ सामने आएँगे, तभी भारत वास्तव में ज्ञान आधारित विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकेगा।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

लोक के प्रति कब जवाबदेह बनेगी नौकरशाही

उमेश चतुर्वेदी

सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 'स्टील फ्रेम' बताया था। संविधान सभा में प्रशासनिक सेवा पर बहस के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मजबूत और तटस्थ नौकरशाही पर जोर दिया था। हालांकि अंग्रेजों के नौकरशाह रह चुके एचवी कामथ को चिंता थी कि वैधानिक सुरक्षा नौकरशाही को गैरजवाबदेह और असल 'शासक' बना सकती है। एक अप्रैल को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना में नौकरशाही ने जैसा रूख अख्तियार किया है, उसे देख लगता है कि पटेल के भरोसे की तुलना में एचवी कामथ की चिंता समय की शिला पर सटीक साबित हुई है। मालदा में पूरे नौ घंटे तक सात न्यायिक अधिकारियों को सियासी कार्यकर्ता के मुखौटे वाले अपराधियों ने बंधक बनाए रखा। उस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मुख्य सचिव से संपर्क करने में नाकाम रहे। दिलचस्प यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब-तलब किया तो उन्होंने माफी मांग कर काम चला लिया। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शीर्ष अधिकारियों को सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह माफी से ही संतुष्ट हो गया। देश को अपने लोकतंत्र पर गर्व है, लेकिन इस व्यवस्था में राजनीतिक तंत्र के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस अफसर लगातार मजबूत हुए हैं। अंग्रेज सरकार ने इंडियन सिविल सेवा यानी आईसीएस का गठन अपने राजकाज को मजबूत करने के लिए किया था। इसलिए शुरूआती दौर में इसमें गोरे लोगों को ही तवज्जो मिली। अंग्रेज सरकार भारतीयों को गुलाम मानती थी, लिहाजा उसके अफसर भी भारतीयों से उसी अंदाज में पेश आते थे। आजादी के बाद नौकरशाही के इस चरित्र को बदलने की कोशिश के तहत तटस्थ ब्यूरोक्रेसी के रूप में आईएएस कैडर बनाया गया। गांधी मानते थे कि आधुनिक राज व्यवस्था और नौकरशाही में हिंसा का वर्चस्व है। गांधी जी 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक या आर्थिक रूप से ताकतवर लोगों से उम्मीद करते थे कि वे संसाधनों के स्वामी नहीं, बल्कि रक्षक की तरह व्यवहार करें। इसी अंदाज में नौकरशाही को सेवक बनाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या नौकराशाह सेवक बन पाए? वे सिर्फ उन राजनीतिक आकाओं के ही सेवक बन पाए हैं, जो ताकतवर हैं और जिनसे उन्हें भविष्य में मलाईदार पदों और ताकत की उम्मीद है। यही वजह है कि आजादी के 79 साल बाद भी नौकरशाही का ज्यादातर हिस्सा सामंती मानसिकता से ही प्रभावित नजर आता है। जनता को वह अपनी रियाया मानता है। लोक से सामंतों जैसा व्यवहार करने में ही उसे हेठी नजर आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला का कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं उठाना इसी सोच का प्रतीक है। यह उस आशंका का भी जीवंत उदाहरण है, जो एचवी कामथ को परेशान कर रही थी। दिलचस्प यह है कि दुष्यंत नरियाला को 16 मार्च को ही चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती की जगह नया मुख्य सचिव बनाया था, ताकि वे निष्पक्ष चुनाव करा सकें। नरियाला के व्यवहार से साफ है कि न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में उनका रवैया तटस्थ नौकरशाह की बजाय राज्य की मौजूदा सत्ता के इशारे पर ही काम करने वाले जैसा रहा।

लोकतंत्र, लोक यानी आम लोगों का तंत्र है। लेकिन हकीकत में यह राजनीतिक दलों का तंत्र है और इस तंत्र में लोक की भूमिका महज वोट देने तक ही सीमित है। इस तंत्र में नौकरशाही की जवाबदेही राजनीति के हर अच्छे-बुरे कामों में साथ देने और कई बार उसका कहार बनने तक सीमित रह गई है। सरदार पटेल जब इस तंत्र को स्टील फ्रेम कह रहे थे, तो उनका आशय यह था कि भावी नौकरशाही आम लोगों की भलाई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। पटेल को उम्मीद रही होगी कि नौकरशाह लोक के प्रति जब जवाबदेह होंगे, तब ऐश्वर्य पर उनकी निगाह कम होगी। लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है। नौकरशाही के बड़े हिस्से को अपनी मूल भूमिका की चिंता नहीं सताती।

बोध कथा

हर बुराई में अच्छाई खोज सकते हैं

एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा - क्यों ना यहां का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा- वाकई जल तो गंगाजल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला- गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है।

आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले- बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ। इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा। पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया, तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहां तक आते-आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना।

व्यंग्य केसरी

चुनावी तपन से त्रस्त नेताजी ...

डॉ. मुकेश गर्ग 'असीमित'

चुनाव सम्पन्न हुए। नेताजी गर्मी की तपन से ज्यादा चुनावी तपन से लथपथ और त्रस्त, लेकिन अब जैसे कि बेटी का ब्याह सम्पन्न हुआ—इसी भाव से अपने चेहरे को पोंछते हुए राहत की कोई साँस लेने ही वाले थे कि चुनावी सर्वे ने वापस नेताजी को पसीने-पसीने कर दिया। लंपट बयानबाज़ी, सैंध, गुटबाज़ी—जितने भी पापड़ थे, सब बेल लिए थे नेताजी ने, लेकिन चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि हार निश्चित है। नेताजी की हालत बिगड़ने लगी।

नेताजी और कोई नहीं, पार्टी अध्यक्ष हैं—वे ऐसे कैसे मान लें इन सर्वे को! मौका पाकर एक कार्यकर्ता कूद पड़ा नेताजी के पास— 'सब विपक्ष की साजिश है ये!'—और नेताजी के पीले पड़े चेहरे पर भ्रम की एक पॉलिश चिपकाने की कोशिश करने लगा।

'नहीं, ये हो नहीं सकता!'—जिस जनता का पाँच साल खून पीने में खून-पसीना एक किया, आज वही इस बार किसी और पार्टी को मौका दे रही है—यह सोचकर ही नेताजी खून का घूँट पीकर रह गए। पार्टी के अध्यक्ष हैं, सत्ता की मलाई खाई है जिन कटोरों में, अब उन कटोरों को कैसे दूसरी पार्टी के आगे सरका दें—यही दुविधा शायद उन्हें परेशान कर रही है।

लेकिन नेताजी ने पैंतरा बदला। इस स्थिति में क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए—यह उन्हें अनुभव है। हार-जीत, दोनों ही पालों में गेंद जाए—दोनों की तैयारियों का पूरा खाका बना हुआ है।

नेताजी ने सभी तैयारियाँ करने के आदेश दे दिए। चिंतन-मनन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया गया। हारने के कारण, जो आकस्मिक योजना के तहत पार्टी ने पहले ही तैयार रखे थे, वे सब ताज़ा कर लिए गए हैं—मसलन ईवीएम में गड़बड़ी, विपक्ष का धनबल, बाहुबल का प्रयोग आदि।

कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों से भी बात चलाने को कहा गया है। नेताजी गणित बिठा रहे हैं कि अगर दस विधायक विपक्ष पार्टी के तोड़ लिए जाएँ, तो बात जमी रह सकती है। इस पर भी मंथन करने के लिए कुछ पार्टी के स्थायी 'बुजुर्ग मंथनकर्ता' लगा दिए गए हैं।

तभी एक मंत्री जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की हदों को पार करके पार्टी के चुनाव में जी-तोड़ फंड मैनेज किया है, वे बड़े विचलित से पार्टी अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं—

'सर, मेरा क्या होगा? मेरे मंत्रालय में घोटालों की फाइलों का अंबार लगा हुआ है। इस पार्टी को जानते नहीं आप—सबसे पहले जांच कराएंगे, फाइलें खुलेंगी, हम सब जेल में सड़ जाएंगे, सर!'

पार्टी अध्यक्ष मुस्कराए—

'आपको पता है ना, गर्मी कितनी भीषण है? मंत्रालय में शॉर्ट सर्किट हो जाना, खासकर इन गर्मियों में, आम बात है... आप चिंता न करें। भगवान ने चाहा तो आज रात ही शॉर्ट सर्किट से आग लग ही जाएगी।

इतिहास

29 अप्रैल का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले की नींव रखने और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। यह दिन वैज्ञानिक और सामाजिक बदलावों के लिए भी जाना जाता है। 29 अप्रैल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं: लाल किला (दिल्ली) की नींव (1639): मुगल बादशाह शाहजहाँ ने आज ही के दिन दिल्ली में अपने निवास के लिए लाल किले की नींव रखी थी। विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक (2001): डेनिस टीटो (Dennis Tito) पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने, जो रूसी रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए रवाना हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस: नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अबू ग़रीब यातना तस्वीरें (2004): बगदाद की जेल में अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई ।

भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा, वैश्विक स्तर पर शांति कायम करने में निभा सकता है बड़ी भूमिका: ग्लोबल एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली। भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और वैश्विक स्तर पर छवि विश्व शांति व्यवस्था को आकार देने वाले, आर्थिक स्थिरता और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाले देश की बन रही है। यह बयान बुधवार को ग्लोबल एक्सपर्ट्स की ओर से दिया गया।

राष्ट्रीय राजधानी में इकोनॉमिस्ट एंटरप्राइज के 'रेजिलिएंट फ्यूचर्स समिट 2026' के साइडलाइन के दौरान आईएएनएस से ??बातचीत में उन्होंने भू-राजनीतिक अनिश्चितता से निपटने, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और एआई और उभरती टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने में भारत के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया।

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में अर्थशास्त्र के ली का शिंग प्रोफेसर डैनी क्वाह ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद की बदलती प्रकृति और व्यापारिक गतिशीलता में आए बदलावों ने विश्व अर्थव्यवस्था में काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है।

क्वाह ने कहा कि व्यापारिक व्यवधानों से परे, एक गहरी चिंता वैश्विक विश्वास में कमी और बहुपक्षीय प्रणालियों का कमजोर होना है, जो पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आधार रही हैं।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है और अगर भारत कोशिश करे तो शांति कायम होगी। लोग शांति लाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग उचित नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। उचित नेतृत्व क्या होगा, यह तय करना अभी भारत पर निर्भर है।'

वहीं, लंदन के विज्ञान संग्रहालय के निदेशक इयान ब्लैचफोर्ड ने एआई के प्रति भारत के विशिष्ट और आशावादी दृष्टिकोण का जिक्र किया।

ब्लैचफोर्ड ने कहा, 'अगर आप अमेरिका और यूरोप के सार्वजनिक सर्वेक्षणों को देखें, तो अधिकांश आबादी एआई को लेकर चिंतित है।

भारत में स्थिति इसके विपरीत है। भारत एआई केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण कर रहा है और साथ ही इसके प्रभावों पर गहराई से विचार भी कर रहा है।'

ब्लैचफोर्ड ने वैश्विक दक्षिण की व्यापक उपलब्धियों, विशेष रूप से भारत की विकास यात्रा की सराहना की।

ब्लैचफोर्ड ने आईएएनएस को बताया, 'देश आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि वह ऊर्जा की बढ़ती मांग जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है।

' उन्होंने आगे कहा, 'यह पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है, जिन्हें दशकों से समृद्धि का लाभ मिल रहा है।

बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 609 अंक चढ़ा, निफ्टी 0.76 प्रतिशत उछला

मुंबई । पश्चिम एशिया तनावों के बीच पिछले दिन की गिरावट के बाद हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली करने के चलते प्रमुख बेंचमार्क दिन के उच्चतम स्तर से तेजी से नीचे आ गए।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 609.45 अंकों यानी 0.79 प्रतिशत की उछाल के साथ 77,496.36 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 181.95 (0.76 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 24,177.65 पर ट्रेड करता नजर आया।

दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 77,245.83 पर खुलकर 77,982.51 का इंट्रा-डे हाई और 77,136.20 का इंट्रा-डे लो बनाया। जबकि निफ्टी50 24,096.90 पर खुलकर 24,334.70 का इंट्रा-डे हाई और 24,059.95 का इंट्रा-डे लो बनाया।

दिन की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई, लेकिन ऑटोमोबाइल और शेयर बाजार में जोरदार उछाल के चलते शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी आई। हालांकि, सत्र आगे बढ़ने के साथ बाजार इस गति को बरकरार नहीं रख सका और अपने अधिकांश लाभ गंवा बैठा।

व्यापक बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप ने 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। सेक्टरवार देखें तो निफ्टी एफएमसीजी में 1.75 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी में 1.48 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो में 1.15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

इसके अलावा, निफ्टी आई में 0.99 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.71 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 0.50 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मीडिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी पीएसयू बैंक कमजोरी के साथ बंद हुए।

निफ्टी 50 पैक में आईटीसी, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, मारुति, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, एमएंडएम और आयशर मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई और ये टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जबकि इंडिगो, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे।

अमेरिकी फेड के फैसले से पहले सोना और चांदी में मामूली तेजी

मुंबई । अमेरिकी फेड के फैसले से पहले बुधवार को सोना और चांदी मजबूती के साथ खुले। इस दौरान दोनों कीमती धातुओं में एक सीमित दायरे में कारोबार देखा गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 जून, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,50,027 रुपए के मुकाबले 693 रुपए या 0.46 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,720 रुपए पर खुला।

हालांकि, 9:55 पर यह 19 रुपए या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,50,008 रुपए पर था।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,49,720 का न्यूनतम स्तर और 1,51,527 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ।

चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,42,763 रुपए के मुकाबले 826 रुपए या 0.34 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,43,589 रुपए पर था।

खबर लिखे जाने तक यह 712 रुपए या 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,43,475 रुपए पर था।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,42,972 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,43,835 रुपए का उच्चतम स्तर बनाया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। सोना 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,616 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.81 प्रतिशत की मजबूती के साथ 73.81 डॉलर प्रति औंस पर थी।

जानकारों के मुताबिक, ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड का फैसला देर रात आएगा। यह फैसला ऐसे समय पर आ रहा है, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई का खतरा बना हुआ है।

अगर ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर फेड को टिप्पणी करता है तो यह सोने के लिए नकारात्मक हो सकता है और इससे आने वाले समय में कीमतों में दबाव देखने को मिल सकता है।

वैश्विक अस्थिरता के चलते सोने और चांदी ने बीते एक साल में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान डॉलर में सोने ने करीब 40 प्रतिशत और चांदी ने 120 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

मध्य पूर्व में तनाव के बाद भी निर्यातकों में उत्साह बरकरार, हॉर्मुज के बंद होने से अलग-अलग मार्गों से हो रहा निर्यात: पीयूष गोयल

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि मध्य पूर्व में तनाव के बाद भी निर्यातकों का उत्साह बना हुआ है और हॉर्मुज के बंद होने के बाद भी अलग-अलग मार्गों से निर्यात किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने मार्गों का जिक्र नहीं किया।

एक कार्यक्रम के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा, 'मध्य पूर्व में युद्ध के बावजूद निर्यातकों में जबरदस्त उत्साह है। अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में हमारा निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी बढ़ा है। जैसे-जैसे नए ट्रेड एग्रीमेंट अमल में आ रहे हैं। निर्यातकों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने से भारतीय निर्यातकों के लिए विश्व के दो-तिहाई बाजार खुल चुके हैं। इससे ऑटो, ऑटो पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सीफूड और सर्विस सेक्टर में अवसर बढ़ रहे हैं।

अमेरिका-भारत एफटीए पर गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते हमारी टीम बातचीत के बाद वहां से लौटी है और चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

फरवरी 2026 में अमेरिका और भारत में एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था और दोनों देशों ने व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए सहमति जताई थी।

इससे पहले गोयल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समझौता केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई नए क्षेत्रों में अपार संभावनाएं खुलेंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर अब शून्य (जीरो) शुल्क लगेगा, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस समझौते के जरिए न्यूजीलैंड का बाजार भारत के लिए लगभग 140 सेवा क्षेत्रों में खुल गया है। इसके अलावा शिक्षा, खेल, संस्कृति, कृषि उत्पादकता और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के शीर्ष शहरों में वेयरहाउसिंग की मांग 2026 की पहली तिमाही में 8 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। भारत के शीर्ष शहरों में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की मांग 2026 की जनवरी-मार्च अवधि में तिमाही आधार पर 8 प्रतिशत बढ़ी है। यह लगातार चौथी तिमाही है, जब मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

वर्कप्लेस सॉल्यूशंस फर्म वेस्टियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर उपभोक्ता धारणा, मजबूत घरेलू मांग और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के समर्थन से वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के 2026 में भी मजबूत रहने की उम्मीद है।

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव, एफआरआईसीएस ने कहा, 'तिमाही आधार पर मांग में वृद्धि मजबूत बाजार को दर्शाती है, जिसे बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और मजबूत घरेलू खपत का समर्थन प्राप्त है। हालांकि,मांग में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, लीजिंग गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, जिसे थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का समर्थन प्राप्त है।

मुंबई और पुणे ने मिलकर कुल लीजिंग गतिविधि में 81 प्रतिशत का योगदान दिया, जो मांग को बढ़ाने में स्थापित पश्चिमी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के निरंतर प्रभुत्व को दिखाता है। लगातार तिमाही आधार पर हो रही रिकवरी से संकेत मिलता है कि 2025 में देखी गई मंदी मांग में संरचनात्मक गिरावट के बजाय रणनीतिक पुनर्संतुलन का एक चरण थी।

मुंबई में सबसे अधिक 4.76 मिलियन वर्ग फुट (कुल लीजिंग का 42 प्रतिशत) वेयरहाउसिंग की मांग की दर्ज किया गया, जबकि पुणे में यह आंकड़ा 4.46 मिलियन वर्ग फुट रहा, जो तिमाही आधार पर 162 प्रतिशत और वार्षिक आधार पर 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

हैदराबाद में वेयरहाउसिंग की मांग 0.69 मिलियन स्क्वायर फीट रही है। इसमें सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में वेयरहाउसिंग की मांग 0.73 मिलियन स्क्वायर फीट रही। इसमें सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की नरमी आई।

चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में वेयरहाउसिंग की मांग क्रमश:0.59 मिलियन स्क्वायर फीट, 0.17 मिलियन स्क्वायर फीट और 0.1 मिलियन स्क्वायर फीट रही।

रिपोर्ट में कहा गया कि आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर बढ़ते जोर, आधुनिक ग्रेड-ए सुविधाओं की बढ़ती मांग और उभरते टियर-I और टियर-II लॉजिस्टिक्स हब में निरंतर विस्तार से 2026 में विकास के अगले चरण को गति मिलने की उम्मीद है।

विलय और विस्तार सौदों का असर! भारत में ट्रांजैक्शनल रिस्क इंश्योरेंस की मांग बढ़ी

नई दिल्ली। बीते वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर विलय और विस्तार सौदों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय कंपनियां की ओर से ट्रांजैक्शनल रिस्क इंश्योरेंस की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह सौदों के पूरे होने और क्रियान्वयन से जुड़ी रिस्क है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

मार्श की रिपोर्ट में कहा गया है कि विलय और अधिग्रहण सौदों का मूल्य वैश्विक स्तर पर सालाना आधार पर लगभग 37 प्रतिशत बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है, जिसमें बड़े सौदों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में भी डील का आकार तेजी से बढ़ रहा है और नियामकीय जांच-पड़ताल ने संरचित जोखिम समाधानों की मांग को तेज कर दिया।

मार्श इंडिया के सीईओ और प्रेसिडेंट संजय केडिया ने कहा, 'जैसे-जैसे भारत खुद को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, लेनदेन से संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने आगे कहा, 'भारतीय डीलमेकर्स के बीच लेन-देन संबंधी जोखिम समाधानों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, खासकर सीमा पार लेन-देन और नियामक जटिलताओं में वृद्धि के कारण। यह ट्रेंड 2026 में और भी तेज होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनियां डील के एग्जीक्यूशन में अधिक लचीलापन और आत्मविश्वास चाहते हैं। रिपोर्ट में ग्लोबल ट्रांजैक्शनल रिस्क इंश्योरेंस लिमिट्स में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़कर 91.6 अरब डॉलर हो गई है। साथ ही, पॉलिसी की मात्रा में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सौदेबाजी के एक प्रमुख घटक के रूप में इंश्योरेंस की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

भारत में निजी इक्विटी और रणनीतिक कॉर्पोरेट लेनदेन, दोनों में ट्रांजैक्शनल रिस्क इंश्योरेंस का प्रचलन बढ़ रहा है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, जहां सौदों का आकार और नियामक संबंधी विचार अधिक गहन हो रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, पीआईबी फैक्ट-चेक यूनिट ने खारिज किया सोशल मीडिया पोस्ट का दावा

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दावा करने वाला आदेश फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया गया कि वे ऐसी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें और अपुष्ट दावों को साझा करने से बचें।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच नागरिकों की चिंताओं को शांत करने का प्रयास किया, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ा है। यहां एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी, हालांकि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आवश्यक ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन भी दिया। शर्मा ने कहा, 'एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए घबराएं नहीं।' उनके अनुसार, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ परिवहन में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की है।

6 घंटे से कम सो रहे हैं? जानिए कैसे आपका दिमाग और दिल चुका रहे हैं इसकी कीमत

रात भर जागकर काम करना या वेब सीरीज देखना अब आम बात हो चुकी है। लेट नाइट जागना अब स्टेटस बनता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह आदत आपको मौत के करीब धकेल रही है? बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे कम सोने वाला देश बन चुका है। भारतीय शहरों में औसत नींद 8 घंटे से घटकर 6 घंटे या उससे भी कम रह गई है। हर 3 में से 1 कामकाजी वयस्क थकान (क्रॉनिक फटीग) की शिकायत करता है, फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं।

लेकिन चिकित्सा विज्ञान की मानें तो नींद की कमी कोई 'स्मार्ट हैक' नहीं, बल्कि एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इस विषय पर जब देश के दिग्गज डॉक्टरों से न्यूज 18 ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि किस तरह नींद से समझौता आपके दिल और दिमाग के लिए घातक होता जा रहा है।

दिमाग चुकाता है सबसे पहले कीमत

डॉ. प्रतिमा मूर्ति (NIMHANS की पूर्व निदेशक) का कहना है कि नींद कोई निष्क्रिय (passive) अवस्था नहीं है। यह एक सक्रिय जैविक मरम्मत प्रक्रिया है। जब आप सोते हैं, तो दिमाग दिन भर जमा हुए जहरीले कचरे को साफ करता है। अगर यह सफाई नहीं होती, तो केवल थकान ही नहीं होती, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता कम होने लगती है और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है।

सलाह देते हुए डॉ. मूर्ति का कहना है कि नींद की स्वच्छता (sleep hygiene) को गंभीरता से लें। रात में हल्का भोजन करें, कैफीन से बचें और सोने से पहले फोन को खुद से दूर रखें। उनका कहना है कि नींद एक बहुत ही कोमल प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।

दिल रखता है हर पल का हिसाब

डॉ. पुरुषोत्तम लाल (मेट्रो हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट) ने नींद की कमी और दिल की बीमारियों के बीच के खतरनाक संबंध को समझाया। उनका कहना है कि नींद की कमी से धमनियों की दीवारें सख्त हो जाती हैं। इससे कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को खतरनाक स्तर पर ले जाते हैं।

डॉ. लाल ने चेतावनी दी कि आज के युवा प्रोफेशनल, प्रेशर और देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत के कारण अपने दिल की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगभग हर हृदय रोगी की मेडिकल हिस्ट्री में नींद की समस्या जरूर पाई जाती है।

पल्मोनोलॉजिस्ट की गंभीर चेतावनी

डॉ. रणदीप गुलेरिया (ϵद्धद्धस्र् दिल्ली के पूर्व निदेशक) ने बताया कि एक पीढ़ी पहले तक इंसान 8-9 घंटे सोता था, जो आज सिमटकर 5-6 घंटे रह गया है। नींद की कमी अपने साथ मोटापा, स्लीप एपनिया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ लेकर आती है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर गर्व से कहते हैं कि वे सिर्फ 4 घंटे सोकर भी ठीक काम कर लेते हैं।

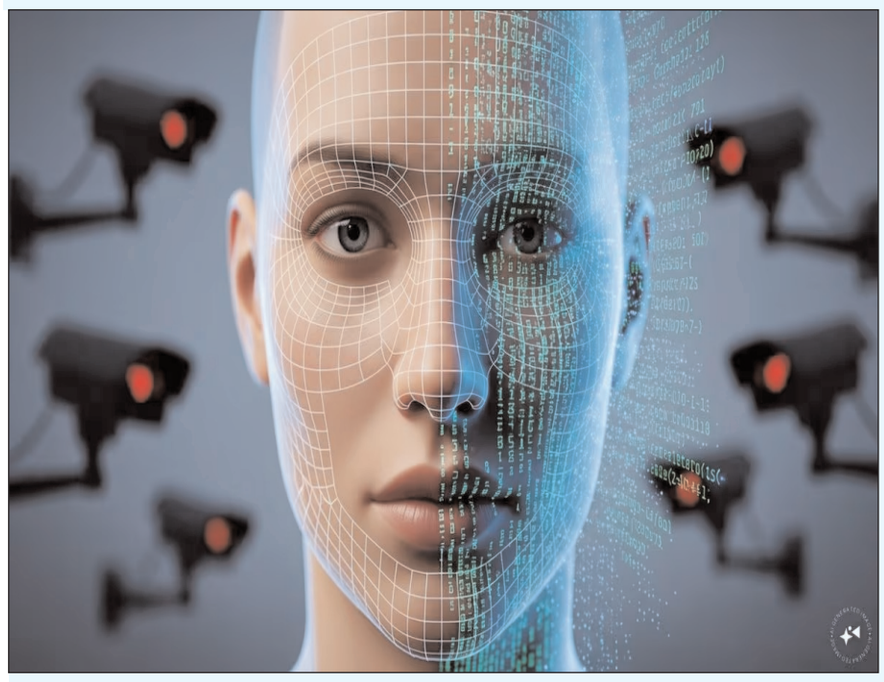

1930 के दशक के जापान से लेकर बिग टेक और एआई तक, 'टेक्नोफैसिज्म' ने कैसे आकार लिया और यह कैसे वैश्विक बन गया

तकनीक और राज्य की शक्ति के बीच चल रही बहस अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। पलान्टिर टेक्नोलॉजीज जैसी डेटा आधारित कंपनियों से जुड़े विवादों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों और रक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ते समझौतों तक, तकनीकी शक्ति के संकेंद्रण पर सवाल उठाना अब कठिन होता जा रहा है। एआई आधारित निर्णय प्रक्रिया, रियल-टाइम निगरानी क्षमताएं और शासन के लिए निजी तकनीकी फर्मों पर बढ़ती निर्भरता रातों-रात पैदा नहीं हुई है। यह तकनीक, डेटा और राज्य के अधिकार के एक साथ आने का एक लंबा और व्यवस्थित विकास है, जो विशेष रूप से अमेरिका में देखा गया है।

टेक्नोफैसिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? टेक्नोफैसिज्म की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिलिकॉन वैली के युग में नहीं हुई थी। इसकी जड़ें आमतौर पर 1930 के दशक के जापान में खोजी जाती हैं, जहाँ तकनीकी विशेषज्ञों के एक समूह ने तकनीकी विशेषज्ञता को राजनीतिक शक्ति के केंद्र में रखकर शासन को नया आकार देना शुरू किया था। आर्थिक तनाव और तेजी से होते औद्योगिकीकरण के उस दौर में, निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित या सार्वजनिक संस्थानों से हटकर इंजीनियरों, योजनाकारों और नौकरशाहों के पास चली गई, जिनका मानना था कि डेटा, सिस्टम और केंद्रीकृत नियंत्रण के माध्यम से समाज को अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सीधे तौर पर राज्य की सैन्य और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा था। योजना निकायों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन, श्रम और संसाधनों का समन्वय करना शुरू कर दिया, जिससे एक नियंत्रित प्रणाली बनी जहाँ आर्थिक परिणाम और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं आपस में गहराई से जुड़ी थीं। मंचूरिया जैसे क्षेत्र इस मॉडल के लिए प्रायोगिक आधार बने, जहाँ प्रशासनिक नियंत्रण, औद्योगिक योजना और निगरानी तंत्र का उपयोग व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया। इस प्रणाली की विशेषता केवल इसका तानाशाही होना नहीं था, बल्कि वह तरीका था जिससे शक्ति काम करती थी। राजनीतिक लामबंदी या करिश्माई नेतृत्व के बजाय, नियंत्रण संस्थानों, नियोजन रूपरेखा और तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से किया गया। शासन का अर्थ सार्वजनिक भागीदारी के बजाय उत्पादन, व्यवहार और परिणामों का अनुकूलन बन गया।

निगरानी बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार निगरानी प्रणाली की जड़ों को 11 सितंबर के हमलों के बाद के वर्षों में देखा जा सकता है। इसके बाद, अमेरिका में सुरक्षा शासन का मुख्य सिद्धांत बन गई। सरकारों ने डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अपनी क्षमता का काफी विस्तार किया, जिसमें अक्सर सार्वजनिक जांच बहुत सीमित रही। भविष्य के खतरों को रोकने की आवश्यकता के नाम पर निगरानी बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा। जो शुरुआत में सीमित निगरानी के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह में बदल गया, जिसने उस प्रणाली की नींव रखी जहाँ सूचना राज्य की शक्ति का केंद्र बन गई। तब भी जोर सुरक्षा पर ही था—जोखिम को ट्रैक करने, पता लगाने और रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में तकनीक का उपयोग।

शक्ति केंद्र के रूप में बिग टेक का उदय जैसे-जैसे निगरानी करने वाला राज्य विस्तृत हुआ, एक और बदलाव यानी बड़ी तकनीकी कंपनियों का उदय हो रहा था। गूगल, फेसबुक और अमेज़ॅन जैसी फर्में केवल उत्पाद नहीं बना रही थीं, बल्कि वे 2000 के दशक की शुरुआत से ही उपयोगकर्ता डेटा का अभूतपूर्व भंडार जमा कर रही थीं। 1995 में एक ऑनलाइन बुकस्टोर के रूप में शुरू हुई अमेज़ॅन ने उपयोगकर्ता के व्यवहार—जैसे लोग क्या देखते हैं, क्या खोजते हैं और क्या खरीदते हैं—को ट्रैक करके अपनी डेटा क्षमताओं का निर्माण शुरू कर दिया। यह जानकारी उसके सुझाव इंजन का आधार बनी। 1998 में शुरू हुए गूगल ने शुरुआत में खोज प्रश्नों को एकत्र करने और विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2007 में डबलक्लिक के अधिग्रहण के बाद इसकी डेटा रणनीति का काफी विस्तार हुआ, जिससे कुकी-आधारित ट्रैकिंग संभव हुई।

एग्जिट पोल कैसे काम करते हैं? पद्धति, गणित और त्रुटि सीमा पर पूरी गाइड

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के साथ पूरी हो गई है। जैसे ही मतदान खत्म होता है, ध्यान तुरंत एग्जिट पोल के लाइव अपडेट्स पर चला जाता है, जो 4 मई 2026 को आने वाले नतीजों के शुरुआती संकेत माने जाते हैं।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के एग्जिट पोल जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। हालांकि केरल, असम और पुडुचेरी में पहले ही मतदान हो चुका था और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन कानूनी प्रतिबंधों के कारण एग्जिट पोल डेटा रोका गया था।

भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, सभी चरणों का मतदान पूरा होने तक एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किए जा सकते। यह प्रतिबंध आज शाम हटेगा—इसीलिए अब सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं।

लेकिन इन भरोसेमंद दिखने वाले अनुमानों के पीछे एक जटिल और मानवीय प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और क्यों कभी-कभी गलत साबित हो जाते हैं।

एग्जिट पोल क्या है और ओपिनियन पोल से कैसे अलग है?

सरल शब्दों में, एग्जिट पोल एक पोस्ट-वोट सर्वे होता है, जिसमें मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। यह सर्वे मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही किया जाता है।

यहां मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया, न कि वे किसे वोट देने वाले हैं। यही एग्जिट पोल और

ओपिनियन पोल में मुख्य अंतर है। ओपिनियन पोल मतदान से पहले अनुमान लगाते हैं, जबकि एग्जिट पोल वास्तविक मतदान व्यवहार को सैंपल के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं।

भारत में एग्जिट पोल चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं और अंतिम चरण तक इन्हें प्रकाशित करने पर रोक रहती है।

भारत में एग्जिट पोल की प्रक्रिया: जमीन पर क्या होता है

सैंपलिंग (नमूना चयन)

एजेंसियां हर बूथ को कवर नहीं कर सकतीं, इसलिए वे कुछ प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों का चयन करती हैं। यह चयन क्षेत्र, पिछला वोटिंग पैटर्न और जनसांख्यिकी के आधार पर होता है।

मैदानी सर्वे

मतदान के दिन एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों के बाहर खड़े होकर वोट डालकर निकल रहे लोगों से संपर्क करते हैं।

मतदाताओं से या तो गुप्त पर्ची भरवाई जाती है या उनके जवाब डिवाइस में दर्ज किए जाते हैं। भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक होती है।

जनसांख्यिकीय डेटा

मतदाता से पार्टी/उम्मीदवार के अलावा उम्र, लिंग, जाति, आय या पेशे जैसी जानकारी भी ली जाती है।

डेटा वेटिंग (समायोजन)

कच्चा डेटा सीधे प्रकाशित नहीं होता। इसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को संतुलित करने के लिए सांख्यिकीय समायोजन किया जाता है।

यहीं पर अलग-अलग एजेंसियों के तरीके अलग होते हैं, जिससे नतीजे भी अलग दिख सकते हैं।

वोट से सीट में बदलना

यह सबसे कठिन चरण है। भारत की 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली में थोड़े से वोट अंतर से कई सीटों का परिणाम बदल सकता है। इसलिए वोट प्रतिशत को सीटों में बदलना बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है।

एग्जिट पोल अलग-अलग क्यों होते हैं?

सैंपलिंग का फर्क: हर एजेंसी अलग बूथ और क्षेत्र चुनती है।

सैंपल का आकार: ज्यादा सैंपल जरूरी नहीं कि बेहतर हो—प्रतिनिधित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सवाल पूछने का तरीका: प्रश्न की भाषा या तरीका जवाब को प्रभावित कर सकता है।

नो-रिस्पॉन्स का प्रबंधन: कई लोग जवाब नहीं देते—इसे अलग-अलग एजेंसियां अलग तरीके से संभालती हैं।

वेटिंग फॉर्मूला: हर एजेंसी का अपना गणित होता है।वोट-से-सीट मॉडल: समान वोट प्रतिशत होने पर भी सीट अनुमान अलग हो सकते हैं।

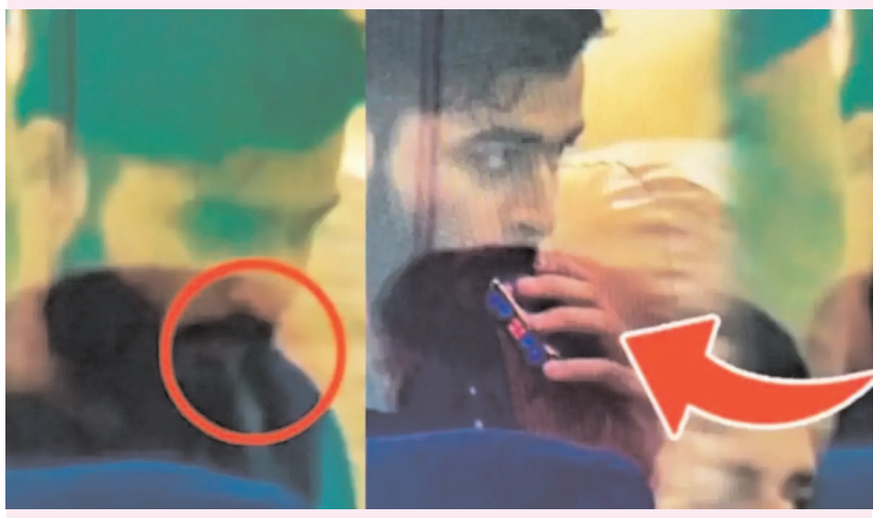

'क्या यह अनुमति है?' रियान पराग का धूम्रपान विराम, राजस्थान टीम को पड़ सकता है भारी

रियान पराग और राजस्थान की टीम एक नए धूम्रपान विवाद में घिर गए हैं, जबकि उन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। पराग की कप्तानी वाली टीम इस सत्र में शीर्ष पर चल रही पंजाब टीम को हराने वाली पहली टीम बनी।

मुल्लांपुर स्थित पीसीए मैदान में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 222 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 59 रन और मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों पर 62 रन की तेज पारी खेली।

जवाब में राजस्थान की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल (51), डोनोवन फरेरा (52) और शुभम दुबे (31*) की पारियों की बदौलत टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली।

मैदान के बाहर विवाद

हालांकि मैच के दौरान सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब कप्तान रियान पराग को विश्राम कक्ष में धूम्रपान करते हुए देखा गया। दूसरी पारी के दौरान यह दृश्य सामने आया, जिससे दर्शक हैरान रह गए।

क्या यह अनुमति है?

भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और उससे संबंधित उपकरणों का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है। यह नियम खेल मैदानों पर भी लागू होता है। इसके अलावा, यह आचरण खेल की गरिमा के विरुद्ध माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी चेतावनी, वेतन में कटौती या निलंबन जैसी कार्रवाई कर सकते हैं।

जन प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद लोगों ने नाराज़गी जताई और इसे लापरवाही तथा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया।

लगातार विवाद

राजस्थान की टीम हाल के समय में कई विवादों में रही है। इससे पहले टीम प्रबंधक को भी मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते देखा गया था, हालांकि बाद में कुछ परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें राहत दी गई।

अंक तालिका

इस जीत के बाद राजस्थान की टीम 9 मैचों में 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि बेंगलुरु की टीम दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

बिरयानी-तरबूज का कॉम्बिनेशन ले सकता है जान? मुंबई में 4 की मौत के बाद डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

हाल ही में मुंबई से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, परिवार ने पहले बिरयानी खाई और उसके बाद तरबूज का सेवन किया। कुछ ही समय में सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और हालत इतनी गंभीर हो गई कि चारों की जान चली गई। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा और गर्मी में खानपान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा,

आइए जानते हैं।

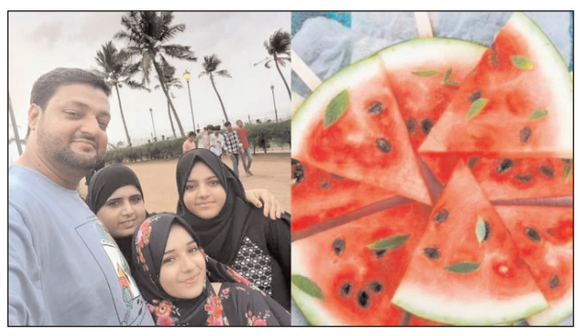

क्या है मौत की बड़ी वजह?

इस मामले पर बात करते हुए Dr. Sanjeev Bagai, जो कि एक जाने-माने पीडियाट्रिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि गर्मियों में खासतौर पर नॉन-वेज भोजन, अगर सही तरीके से पकाया या स्टोर नहीं किया गया हो, तो उसमें खतरनाक बैक्टीरिया पनप सकते हैं। उनके अनुसार, बासी या अधपकी बिरयानी में श्व. ष्र्शद्यद्ब जैसे ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जो शरीर में जाकर गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन और कई मामलों में जानलेवा स्थिति पैदा कर सकते हैं।

तरबूज भी बन सकता है खतरा

डॉ. बगई ने यह भी चेतावनी दी कि बाजार में बिकने वाले फलों, खासकर तरबूज को आकर्षक और मीठा दिखाने के लिए उसमें कृत्रिम रंग और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में इन फलों में इंजेक्शन के जरिए रंग या मिठास बढ़ाने वाले तत्व मिलाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे जहरीले तत्व शरीर में जाकर अचानक गंभीर रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ती है।

गर्मी में बरतें सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि बासी खाना न खाएं, खुले में कटे फल खरीदने से बचें।

निकोटीन की लत से लेकर फेफड़ों के नुकसान तक: वेपिंग के प्रभाव समझिए

पिछले कुछ वर्षों में वेपिंग को अक्सर धूम्रपान का 'सुरक्षित' विकल्प बताकर प्रचारित किया गया है, खासकर युवाओं और पहली बार उपयोग करने वालों के बीच। लेकिन ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तरह तंबाकू नहीं जलातीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। वेपिंग के जरिए शरीर में निकोटीन और अन्य रसायन पहुंचते हैं, जो फेफड़ों, दिल और दिमाग पर गंभीर असर डाल सकते हैं।

वेपिंग क्या है?

वेपिंग में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेप डिवाइस से निकलने वाले

एरोसोल (जिसे आमतौर पर वेपर कहा जाता है) को सांस के साथ अंदर लिया जाता है। इन डिवाइस में एक तरल पदार्थ गर्म किया जाता है, जिसमें आमतौर पर निकोटीन, फ्लेवर और अन्य रसायन होते हैं।

यह तंबाकू नहीं जलाता, इसलिए कुछ जहरीले तत्व कम हो सकते हैं, लेकिन 'कम' का मतलब 'सुरक्षित' नहीं होता।

धूम्रपान इससे कैसे अलग है?

पारंपरिक सिगरेट में तंबाकू जलता है, जिससे धुआं बनता है जिसमें हजारों रसायन होते हैं—जैसे टार और कार्बन मोनोऑक्साइड।

धूम्रपान का सीधा संबंध फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और पुरानी सांस की बीमारियों से है। तंबाकू जलने के कारण इसमें ज्यादा कैंसरकारी तत्व होते हैं। क्या वेपिंग ज्यादा सुरक्षित है? विशेषज्ञ मानते हैं कि वेपिंग में पारंपरिक सिगरेट की तुलना में कुछ कम जहरीले रसायन हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी जोखिम मौजूद हैं।

वेप में निकोटीन, भारी धातुएं, बेहद महीन कण और अन्य हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जो समय के साथ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। निष्कर्ष - वेपिंग, धूम्रपान से कम हानिकारक हो सकती है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। निकोटीन की लत एक बड़ी चिंता सिगरेट और ज्यादातर ई-सिगरेट दोनों में निकोटीन होता है, जो बेहद लत लगाने वाला पदार्थ है।

यह दिल की धड़कन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ।

संघर्ष और सपनों पर खुलकर बोलीं रश्मि देसाई, 'मैं सिंगल हूं, लेकिन मजबूत हूं'

मुंबई। एक्टिंग की दुनिया में कई सितारे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ कलाकार असफलताओं और निजी संघर्षों का सामना करते हुए टूट भी जाते हैं। हालांकि कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर सामने आते हैं। ऐसी ही हैं रश्मि देसाई, जिन्होंने अपने करियर और निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आईएएनएस संग बातचीत में रश्मि ने अपने संघर्ष, सपनों, असफलताओं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने को लेकर खुलकर बात की।

मीडिया से बात करते हुए रश्मि देसाई ने खुद को एक मजबूत सोच वाली सिंगल महिला बताते हुए कहा, 'मैंने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। मेरे लिए जिंदगी में बदलाव आना बिल्कुल सामान्य बात है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच भी है। हर चीज एक समय के बाद बदल जाती है, इसलिए इंसान को भी बदलाव को अपनाना सीखना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी जिंदगी से एक सबसे अहम बात सीखी है और वह है लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर इंसान रुक जाता है तो वह पीछे छूट जाता है, इसलिए मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ना जरूरी होता है। अभिनेत्री ने कहा, ''जैसे-जैसे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं। सपने देखने पर कोई टैक्स खर्च नहीं लगता। इसलिए इंसान को बिना डरे बड़े सपने देखने चाहिए। हर व्यक्ति को खुद को हर कदम पर चुनौती देनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान का काम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है, बाकी चीजें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए।''

रश्मि ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को भी याद किया। उन्होंने कहा, ''मैंने कई बार असफलताओं का सामना किया है।

'हमारी फिल्म को सही तारीख दिलाने के लिए धन्यवाद', वरुण धवन ने केजीएफ फेम यश का जताया आभार

मुंबई। सुपरस्टार और केजीएफ फेम यश की बहुप्रतीक्षित फि?ल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज डेट एक बार फिर से टाल दी गई। इस फैसले के बाद अब वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट में बदलाव किया गया। पहले यह फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे फिर से उसकी पुरानी तय तारीख पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है।

दरअसल, पहले 'टॉक्सिक' को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। इसी वजह से 'है जवानी तो इश्क होना है' के निर्माताओं ने अपनी फिल्म की रिलीज पहले कर दी थी और इसे 22 मई को लाने का फैसला लिया था। माना जा रहा था कि दोनों फिल्मों की रिलीज एक-दूसरे के बेहद करीब होने से बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब जब 'टॉक्सिक' की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है, ऐसे में वरुण धवन की फिल्म को फिर से पुरानी रिलीज डेट 5 जून पर लाया गया है।

फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आने के बाद वरुण धवन ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने अपनी फिल्म के दो नए पोस्टर साझा किए। इन पोस्टरों में उनका अलग अंदाज दिखाई दे रहा है।

पोस्ट साझा करते हुए वरुण धवन ने बताया कि उनकी फिल्म अब 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके साथ ही उन्होंने यश और मैडॉक फिल्म्स का आभार जताया।

वरुण ने कैप्शन में लिखा, 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यश और मैडॉक फिल्म्स का धन्यवाद जिन्होंने हमारी फिल्म की रिलीज डेट तय करने में मदद की। अब यह फिल्म अपनी तय तारीख पर ही रिलीज होगी। आईपीएल के बाद रिलीज होने वाली यह पहली फिल्म है।

हालांकि रिलीज डेट बदलने के बाद अब 'है जवानी तो इश्क होना है' के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब 5 जून को इसकी सीधी टक्कर बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' से होगी। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है।

'लुक्खे' में दिखेगा पलक तिवारी का इमोशनल अवतार, मां श्वेता तिवारी से मिले ये खास एक्टिंग टिप्स

मुंबई। अभिनेत्री पलक तिवारी वेब सीरीज 'लुक्खे' के जरिए ओटीटी पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज रैप कल्चर, स्ट्रीट राइवलरी और बदले की कहानी है।

इस सीरीज में पलक ने सनोबर नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है, जो म्यूजिक और हाई-स्टेक्स वाली दुनिया में अपनी कमजोरियों, प्यार और अंदरूनी संघर्षों से लड़ती नजर आएगी। अपने किरदार को अभिनेत्री का कहना है कि सनोबर काफी भावनात्मक और एक्सप्रेसिव है।

पलक को एक्टिंग विरासत में मिली है। उनकी मां श्वेता तिवारी टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा हैं। दिग्गज अभिनेत्री की बेटी होने के नाते पलक पर हमेशा उम्मीदों का दबाव रहता है। इस बारे में पलक का कहना है, 'बेशक, मेरी मां के शानदार अभिनय की वजह से थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन मेरी नजर में वह सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं।

सीरीज में सनोबर के किरदार को अभिनेत्री पलक तिवारी अपनी मां के मशहूर किरदार 'प्रेरणा' (कसौटी जिंदगी की) के लिए एक ट्रिब्यूट मानती हैं।

अभिनेत्री का कहना है कि प्रेरणा की तरह सनोबर भी बहुत इमोशनल है और अपने दिल की बात खुलकर कहती है। मुझे लगता है कि सनोबर ही असल मायने में प्रेरणा की बेटी की तरह है।

पलक ने बताया कि सीरीज की शूटिंग के दौरान श्वेता ने उन्हें कुछ टिप्स दिए थे। पलक ने बताया कि उनकी मां हमेशा कहती हैं, 'अगर तुम दर्शकों को रुला सकीं, तो समझो तुम एक सफल एक्टर हो। इसके अलावा, मां ने मुझे एक बड़ी सीख दी कि हर सीन को जीतने की कोशिश मत करो।

पलक ने बताया कि उनकी मां का मानना है कि हर सीन का अपना एक हीरो होता है। कभी आपको चमकना चाहिए और कभी अपने साथी कलाकार को मौका देना चाहिए। इसी टीम वर्क से एक सीन और पूरी सीरीज कामयाब होती है।

विपुल डी. शाह और राजेश बहल द्वारा निर्मित सीरीज का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। यह सीरीज 8 मई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।

जापान में रिलीज होगी रणवीर सिंह की 'धुरंधर', क्या तोड़ पाएगी 'आरआरआर' का रिकॉर्ड

मुंबई। आदित्य धर की 'धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है लेकिन आज भी वर्ल्डवाइड कलेक्शन में आमिर खान की फिल्म 'दंगल' से काफी पीछे हैं।

'धुंरधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' दोनों को भी भारत और विदेशों में खूब सारा प्यार मिला। अब फिल्म को जापान में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। 'धुरंधर' को 7 जुलाई को जापान में रिलीज किया जाएगा।

जियो स्टूडियो ने फिल्म 'धुरंधर' का जापानी पोस्टर शेयर किया है और रिलीज की तारीख का ऐलान भी किया है। पोस्टर के मुताबिक फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में फिल्म के सामने बहुत सारी चुनौती है क्योंकि भारत की कई ऐसी फिल्में हैं, जो जापान में बेहतरीन कलेक्शन कर चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि भारत की तरह जापान में भी क्या 'धुरंधर' नया रिकॉर्ड कायम कर पाएगी।

पहले बात करते हैं राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' की, जो जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और अभी तक जापान में आरआरआर की कमाई का रिकॉर्ड कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। फिल्म ने 2.42 बिलियन येन यानी 136 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 'दंगल' ने भले भी चीन में ताबड़तोड़ कमाई की, लेकिन जापान में भी फिल्म का कलेक्शन ठीक-ठाक रहा। अलग जापानी नाम के साथ रिलीज हुई फिल्म ने 12.40 मिलियन येन, यानी लगभग 73.48 लाख रुपये की कमाई की।

वहीं शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को भी जापान में रिलीज किया गया था और फिल्म 1.34 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। फिल्म को बड़ी संख्या में स्क्रीन पर रिलीज किया गया था।

आमिर खान और किरण द्वारा निर्मित हालिया रिलीज फिल्म 'लापजा लेडीज' और प्रभास की 'सालार' ने भी जापान में अच्छी कमाई की थी। छोटे बजट में बनी लापजा लेडीज ने जापान में 2.75 करोड़ की कमाई की थी, जबकि प्रभास की 'सालार' ने 95 लाख रुपए से अधिक की कमाई की थी। अब देखना होगा कि धुंरधर किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होती है।

अर्जुन कपूर पर्सनालिटी राइट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पारित करेगा अंतरिम आदेश, 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार्स पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, और उन्हें मामले में राहत भी मिली है।

अब अभिनेता अर्जुन कपूर द्वारा दायर पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों पर बनी सभी सामग्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वह अपमानजनक न हो। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आम आदमी पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए अदालत नहीं आता। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक चर्चा में होता है तो बहुत कुछ होता है; ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ चीजें अपमानजनक या मानहानिकारक हो सकती हैं, लेकिन हर सामग्री को इस दायरे में नहीं लाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की।

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने एआई के दुरुपयोग और अश्लील सामग्री से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभिनेता के वकील की तरफ से कहा गया कि कई ऑनलाइन साइट्स पर बिना अनुमति के अभिनेता का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और एआई वीडियो के जरिए भी बिना इजाजत उनकी डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले साउथ के बड़े स्टार अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन ने भी पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था। अभिनेता अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के वीडियो और फोटोज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया।

11वें राजदूतों और उच्चायुक्तों के सम्मेलन में एस जयशंकर बोले-देश के हित को आगे बढ़ाने को कूटनीति तैयार

नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को 11वें राजदूतों और उच्चायुक्तों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत के उच्चायुक्त, राजदूत और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया।

सम्मेलन की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'नई दिल्ली में 11वें राजदूतों और उच्चायुक्तों के सम्मेलन में भारत के हाई कमिश्नर, राजदूत और सीनियर एमईए अधिकारियों को संबोधित किया। हमारी बातचीत में पिछले दशक में दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव में हुई काफी बढ़ोतरी को पहचाना गया। एक अस्थिर और उथल-पुथल भरी दुनिया में, भारतीय डिप्लोमेसी देश के हित को आगे बढ़ाने और देश के लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है।'

इससे पहले डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को इक्वाडोर की अपनी समकक्ष गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, कृषि और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

इसके अलावा, विदेश मंत्री सोमरफेल्ड ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड रोसेरो का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो भारत के अपने पहले दौरे पर हैं। हमने व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल और कैपेसिटी बिल्डिंग सहित सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। बहुपक्षीय फोरम में मिलकर सहयोग करेंगे।'

उन्होंने भारत के नेतृत्व वाले इसरो सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने के इक्वाडोर के फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि इक्वाडोर पहले से ही कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सदस्य है। विदेश मंत्री ने यह भी घोषणा की कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए फंडिंग को लेकर एक समझौता हो गया है।

एस जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को इक्वाडोर की अपनी समकक्ष गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, कृषि और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा, विदेश मंत्री सोमरफेल्ड ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड रोसेरो का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

नेपाल की नई 'वेलनेस टूरिज्म' रणनीति, 2030 तक दस हजार पर्यटकों का लक्ष्य

काठमांडू। नेपाल में पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और एडवेंचर टूरिज्म लंबे समय से पर्यटन उद्योग की पहचान रहे हैं, लेकिन अब नेपाली सरकार वेलनेस टूरिज्म को भी अपने मुख्य स्तंभों में शामिल करना चाहती है।

इसी उद्देश्य से संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 'नेशनल वेलनेस टूरिज्म स्ट्रैटेजी (2026-2035) और एक्शन प्लान (2026-2030)' शुरू किया है। इसका मकसद नेपाल को वेलनेस, आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक आकर्षक जगह बनाना है, ताकि पर्यटन उत्पादों में विविधता आए और प्रतिस्पर्धा बढ़े। देश का लक्ष्य है कि 2030 के बाद हर साल 10,000 से ज्यादा वेलनेस पर्यटक आएं और 20 से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हो।

वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि साल 2027 को 'वेलनेस टूरिज्म ईयर' के रूप में मनाया जाएगा। 15 अप्रैल को देश ने पहला 'वर्ल्ड वेलनेस डे' भी मनाया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है और इसमें नेपाल की बड़ी भूमिका रही। इस रणनीति में चार मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: स्पा और मसाज सेवाएं, आयुर्वेद क्लीनिक, योग व ध्यान और प्राकृतिक उपचार व आध्यात्मिकता। योजना के अनुसार, नेपाल में कम से कम पांच प्रमुख जगहों पर इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और पर्यटकों की संतुष्टि बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वेलनेस पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। 2026-27 में पहले चरण में 500 से 1,000 विदेशी पर्यटकों को लाकर सुविधाओं का परीक्षण किया जाएगा। दूसरे चरण (2028-29) में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और 3,000 से 5,000 विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 के बाद इस रणनीति का लक्ष्य होगा कि नेपाल वेलनेस टूरिज्म के एक मजबूत और विकसित बाजार के रूप में उभरे और 10,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक हर साल आने लगें।

इस रणनीति में 2027 तक वेलनेस टूरिज्म के लिए ब्रांड पहचान और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की भी योजना है। साथ ही 'आरोग्य नेपाल' (वेलनेस नेपाल) नाम से एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया जाएगा।

बांग्लादेश में मानवाधिकार ढांचे और हिरासत में यातना पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

ढाका। संयुक्त राष्ट्र की यातना मामलों की विशेष प्रतिवेदक ऐलिस एडवर्ड्स ने बांग्लादेश में एक 'ए-स्टेटस' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमी और हिरासत में यातना रोकने के लिए राष्ट्रीय रोकथाम तंत्र न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा बहुत गहराई से व्यवस्थित रूप से और लंबे समय से मौजूद है। उन्होंने यह बातें ढाका के होटल हॉलिडे इन में आयोजित एक सलाहकार बैठक में कहीं। बैठक का उद्देश्य बांग्लादेश में यातना रोकने और जवाबदेही बढ़ाने के ढांचे को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश लीगल एड सर्विसेज ट्रस्ट, एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर, इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन काउंसिल फॉर टॉर्चर विक्टिम्स और रेड्रेस ने मिलकर किया था। विशेष प्रतिवेदक, जो इस समय बांग्लादेश के एक सप्ताह के अध्ययन दौरे पर हैं, ने कहा कि देश के पास एक मजबूत 'कानूनी ढांचा' तो है, लेकिन उसका सहायक ढांचा अधूरा है। यह बात बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने रिपोर्ट की। उन्होंने कानूनी ढांचा का मतलब बताया कि बांग्लादेश के संविधान में यातना पर रोक है, देश ने 'कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर' को मंजूरी दी है, और 2013 में यातना को अपराध घोषित करने वाला कानून भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी सबसे बड़ी कमी एक 'ए-स्टेटस' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है, जो ग्लोबल एलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के मानकों के अनुसार हो। यातना को रोकने के लिए पुलिस हिरासत में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है।

रिपोर्ट : अत्याधिक खाद्य संकट झेलने वाले टॉप 10 देशों में बांग्लादेश शामिल

नई दिल्ली। '2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस' (जीआरएफसी) के अनुसार, वर्ष 2025 में उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले शीर्ष 10 देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। यह जानकारी ढाका स्थित समाचारपत्र द डेली स्टार में प्रकाशित एक लेख में दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 1.6 करोड़ लोग संकट स्तर की खाद्य असुरक्षा या उससे भी बदतर स्थिति का सामना कर रहे थे। यह विश्लेषित आबादी का करीब 17 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह विश्लेषण देश की कुल आबादी के केवल 59 प्रतिशत हिस्से पर आधारित था, पूरी आबादी पर नहीं।

ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. सलीम रायहान ने अपने लेख में कहा है कि खाद्य असुरक्षा की लगातार बनी रहने वाली स्थिति एक गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करती है। इसके पीछे कम और अस्थिर आय, कमजोर क्रय शक्ति, क्षेत्रीय असमानता, जलवायु जोखिम, पोषण संबंधी कमजोर परिणाम और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कमियां जैसी वजहें हैं।

उन्होंने कहा कि कई परिवारों के लिए समस्या यह नहीं है कि बाजार में भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह है कि भोजन उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पौष्टिक आहार महंगा है और लोगों के पास संकट से निपटने के साधन भी खत्म हो चुके हैं।

लेख में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश में खाद्य महंगाई ने परिवारों के व्यवहार को बदल दिया है। कई परिवारों ने प्रोटीन युक्त भोजन कम कर दिया है, सस्ते अनाजों पर निर्भरता बढ़ा दी है, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च टाल दिया है, अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लिया है और बच्चों की जरूरतों में कटौती की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब चावल, खाद्य तेल, दाल, अंडे, मछली और सब्जियां लंबे समय तक महंगी बनी रहती हैं, तो इसका असर पोषण स्तर पर पड़ता है। बच्चे चुपचाप कुपोषण का शिकार होते हैं। महिलाएं अक्सर सबसे अंत में खाना खाती हैं और कम खाती हैं। गरीब परिवारों के बुजुर्ग अनियमित सहायता पर अधिक निर्भर हो जाते हैं।

लेख में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2025 में प्रवासी आय (रेमिटेंस) से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। रेमिटेंस का लाभ सभी क्षेत्रों और परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुंचता। यह कई परिवारों को सहारा देता है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति का विकल्प नहीं हो सकता।

ईरान और लेबनान में सीजफायर कूटनीतिक कोशिशों के जरिए बनाए रखना होगा: ईसी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के बाद दोनों पक्षों के बीच स्थायी समाधान की कूटनीतिक कोशिशों लगातार जारी है। दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ईरान और लेबनान में सीजफायर को कूटनीतिक कोशिशों से बनाए रखना होगा। उन्होंने आगे कहा, 'हमारा लक्ष्य युद्ध को हमेशा के लिए खत्म होते देखना है और होर्मुज स्ट्रेट में बिना किसी फीस के नेविगेशन की पूरी आजादी वापस लाना है।'

उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते में ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ध्यान देना चाहिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के नतीजे यूरोप में आर्थिक सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं।

ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के यूएन दूत आमिर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी है कि इजरायल क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक लगातार और गंभीर खतरा बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने इजरायल के सीजफायर उल्लंघन और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जिक्र किया।

ईरानी दूत ने कहा कि पश्चिम एशिया में असली कलेक्टिव सिक्योरिटी पाने के लिए एक एकजुट जवाब की जरूरत है जो अस्थिरता के मुख्य सोर्स यानी इजरायल के कब्जे वाले शासन से सीधे तौर पर निपटे।

ईरान ने मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से 21 लोगों को फांसी दी और 4,000 गिरफ्तार : यूएन

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हमले शुरू होने के बाद से ईरान ने कम से कम 21 लोगों को फांसी दी है और 4,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव देखने को मिला।

यूएन राइट्स के ऑफिस ने कहा, 'अमेरिका-इजरायली हमलों की वजह से लड़ाई शुरू होने के बाद से जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में कम से कम नौ लोगों को फांसी दी गई है। इसके अलावा दस को विपक्षी समूह में कथित तौर पर शामिल होने के लिए और दो को जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है।'

एजेंसी ने एक बयान में कहा, '28 फरवरी से अब तक ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों में 4,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।'

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान को नई चेतावनी दी है। ट्रंप ने दावा किया, 'ईरान अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है। जल्द ही होशियार हो जाओ। उन्हें नहीं पता कि नॉन-न्यूक्लियर डील पर साइन कैसे करना है।'

वहीं, होर्मुज संकट के बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को ईरानी बंदरगाहों की लंबी नाकाबंदी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मंगलवार देर रात रिपोर्ट दी कि ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाली शिपिंग को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था और तेल एक्सपोर्ट को दबाना जारी रखने का फैसला किया है।

ईरान के यूएन दूत, आमिर सईद इरावानी ने यूएन महासचिव और सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के ईरानी जहाजों पर कब्जा करने का कड़ा विरोध किया है और इस काम को पाइरेसी बताया है।

ईरानी की अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने लेटर में कहा, 'घरेलू इंतजामों पर भरोसा करना, जो असल में गैर-कानूनी हैं, किसी भी हालत में ताकत के इस्तेमाल से किए गए ऐसे घिनौने जुर्म को सही नहीं ठहरा सकता।'

एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी पर ट्रंप को कथित धमकी देने के आरोप में केस दर्ज

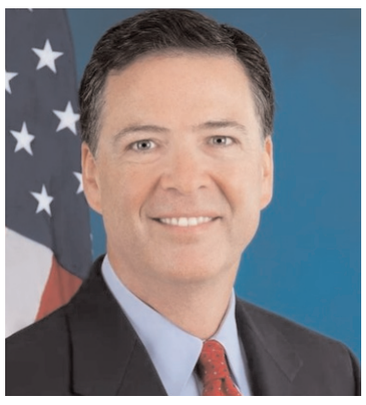

वाशिंगटन। अमेरिका में एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। यह आरोप-पत्र नॉर्थ कैरोलिना के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में दाखिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 15 मई 2025 को कोमी ने जानबूझकर राष्ट्रपति की हत्या करने और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। साथ ही, उन पर एक राज्य से दूसरे राज्य तक धमकी भरा संदेश भेजने का भी आरोप है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला एक इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें सीपियों को '86 47' नंबरों के रूप में सजाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि हालात को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इसे राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने के इरादे के रूप में देख सकता है। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि यह केस महीनों की जांच के बाद दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को धमकी देना हमारे देश के कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। माहौल को शांत करने की जरूरत है, और जो कोई भी इसे भड़काएगा और राष्ट्रपति की जान को धमकी देगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।'

होर्मुज शिपिंग पर हमलों की भारत ने की निंदा, फ्री नेविगेशन फिर से शुरू करने की उठाई मांग

संयुक्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग पर हुए हमलों की निंदा की और फ्री नेविगेशन को फिर से शुरू करने की मांग की है। होर्मुज स्ट्रेट भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।

भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया, 'कमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री हमलों का टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए, और ऐसी कोशिशें बहुत बुरी हैं।'

पटेल ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ईरान की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाया कि भारत ने बहरीन के लाए गए काउंसिल के एक प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया था, जिसमें मिडिल ईस्ट पड़ोसियों पर तेहरान के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी।

उन्होंने कहा, 'इस मामले में यह बताना जरूरी है कि भारत ने यूएनएससी प्रस्ताव 2817 को को-स्पॉन्सर किया था, जिसे 11 मार्च को अपनाया गया था।' बता दें, ईरान ने भारतीय जहाजों और वहां जा रहे एक जहाज पर हमला किया है। इसके साथ ही दूसरे देशों के जहाजों पर हमलों में कम से कम तीन भारतीय नाविक मारे गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने होर्मुज इलाके में नाकाबंदी कर दी। पटेल ने मिडिल ईस्ट के हालात पर काउंसिल प्रेसिडेंट बहरीन की बुलाई मीटिंग में कहा, 'हम इस बात पर जोर देते हैं कि कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना और बेकसूर सिविलियन क्रू मेंबर्स को खतरे में डालना या होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन और कॉमर्स की आजादी में रुकावट डालना मंजूर नहीं है।'

रिपोर्ट : कृषि क्षेत्र की गहरी कमजोरियों के कारण पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा गंभीर, शीर्ष 10 देशों में शामिल

इस्लामाबाद। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 10 देशों में शामिल किया गया है, जहां अत्याधिक खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक केंद्रित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति देश के कृषि क्षेत्र की गहरी जड़ें जमा चुकी कमजोरियों, बार-बार आने वाले जलवायु संकटों और लगातार आर्थिक अस्थिरता का परिणाम है।

'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026' के अनुसार, पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा अस्थायी या चक्रीय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक समस्या बन चुकी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में सबसे गंभीर श्रेणियों में आने वाले लोगों की संख्या कुछ कम हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि आपातकालीन राहत उपायों और कीमतों में कुछ स्थिरता का असर पड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के संपादकीय में कहा गया है कि बड़े कृषि आधार वाले देश के लिए यह निष्कर्ष चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा का यह स्तर कृषि व्यवस्था की पुरानी कमजोरियों का अनुमानित नतीजा है, जिसे जलवायु आपदाओं और आर्थिक संकटों ने और बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 1.1 करोड़ से अधिक लोग अब भी तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें 93 लाख लोग 'संकट' की स्थिति में हैं, जबकि 17 लाख लोग 'आपातकाल' श्रेणी में हैं। यह आंकड़ा बताता है कि देश की सामाजिक और आर्थिक सहनशीलता बहुत सीमित रह गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु अस्थिरता पाकिस्तान में संकट को और बढ़ाने वाला प्रमुख कारक बनी हुई है। बार-बार आने वाली बाढ़ और चरम मौसम घटनाओं से फसलें बर्बाद हुई हैं और ग्रामीण आजीविका प्रभावित हुई है।

जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल : पीयूष गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई में भारत विश्व स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है और नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से आठ साल पहले ही हासिल कर चुका है। देश अब 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में 'जलवायु परिवर्तन के साथ लचीलेपन को बढ़ावा देना' विषय पर आयोजित संवाद में अपने मुख्य भाषण में मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) हासिल करने में मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, क्योंकि भारत लगातार जी20 देशों में टॉप तीन देशों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले 9-10 वर्षों में 20 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया और समय पर हासिल कर लिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अब 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पेरिस कॉप 21 में भारत के नेतृत्व को याद करते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों को एक साथ लाकर सर्वसम्मति से एक ऐसा निष्कर्ष निकाला, जिससे देशों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक नकारात्मक सोच वाले देश से वैश्विक नेता के रूप में विकसित हुई।

भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कई देश और क्षेत्र व्यापार और आर्थिक साझेदारी के लिए भारत के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेरू, चिली, कनाडा, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, ब्राजील और उसके पड़ोसी देश, रूस और यूरेशिया रीजन और इजरायल सहित 12 अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ भी बातचीत जारी है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, पीआईबी फैक्ट-चेक यूनिट ने खारिज किया सोशल मीडिया पोस्ट का दावा

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दावा करने वाला आदेश फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।'

पीआईबी फैक्ट चेक ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया गया कि वे ऐसी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें और अपुष्ट दावों को साझा करने से बचें।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच नागरिकों की चिंताओं को शांत करने का प्रयास किया, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ा है। यहां एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी, हालांकि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आवश्यक ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन भी दिया।

संक्षिप्त खबर

चेन्नई में अंतर-राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 200 किलोग्राम गांजा जब्त

चेन्नई। भारत सरकार के 'नशा मुक्त भारत' अभियान को आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चेन्नई जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई में अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के तहत 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

साथ ही, तस्करी में इस्तेमाल किया गया एक आइशर ट्रक भी जब्त किया गया है और अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई 26 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के नल्लूर टोल प्लाजा के पास की गई, जहां एनसीबी अधिकारियों ने तेलंगाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सक्रिय था और बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तमिलनाडु के तूतीकोरिन क्षेत्र के निवासी हैं। इस गिरोह का सरगना नागेंद्रन उर्फ रघु, जो तिरुपुर के कुमार नगर का रहने वाला है, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में विरुधुनगर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसमें उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित था। इसके अलावा, 2024 में मदुरै में आर्म्स एक्ट और 2025 में करूर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब्त किया गया गांजा ओडिशा के मलकानगिरी जिले से लाया गया था और आंध्र प्रदेश के रास्ते तमिलनाडु पहुंचाया जा रहा था। इस खेप का उद्देश्य कोयंबटूर में कॉलेज के छात्रों और कामकाजी युवाओं के बीच इसकी आपूर्ति करना था। तस्करों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए एक खास तरीका अपनाया था। गांजे को प्लास्टिक कचरे की खेप के अंदर छिपाकर ट्रक में लादा गया था, ताकि संदेह से बचा जा सके।

पांडव कुमार के घर पहुंचे विधायक संजीव झा, सरकार से एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा दिल्ली पुलिस की गोलियों से जान गंवाने वाले पांडव कुमार के घर पहुंचे। पांडव कुमार मूलत: बिहार के खगड़िया का रहने वाला था, जो जोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था।

संजीव झा ने पांडव कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। साथ ही, उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। विधायक ने कहा कि पांडव कुमार अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता था। उसकी मौत ने परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया।

विधायक संजीव झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने मुलाकात की कई तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें वो पांडव कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं।

उन्होंने पुलिस द्वारा मारी गई गोली को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में घटी बेहद दुखद और शर्मनाक घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 'बिहार' का नाम सुनते ही दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल द्वारा युवक को गोली मार देना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि हमारे समाज में फैली संकीर्ण सोच और भेदभाव को भी उजागर करता है।'

उन्होंने कहा, 'आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। इस दौरान मेरे साथ महाबल मिश्रा (पूर्व सांसद), विनय मिश्रा (पूर्व विधायक, द्वारका) और पूजा बाल्यान धर्मपत्नी नरेश बाल्यान (पूर्व विधायक, उत्तम नगर) भी मौजूद रहीं।'

विधायक ने आगे कहा, 'मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। ऐसे में हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।' उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।'

राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को राहत, मेडिकल कारणों से 25 मई तक बढ़ी जमानत

जोधपुर/अहमदाबाद। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत को चिकित्सा कारणों से 25 मई तक बढ़ा दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसकी अवधि मई की शुरुआत में समाप्त होने वाली थी। अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम राहत 25 मई तक या उच्च न्यायालय द्वारा उनकी लंबित आपराधिक अपील पर फैसला सुनाए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। आसाराम की ओर से पेश हुए अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने बताया कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। आसाराम का इलाज अभी जारी है, इसलिए इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।' राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने अंतरिम जमानत की अवधि को और आगे बढ़ाने के खिलाफ तर्क दिया। 84 वर्षीय आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद से 2018 से आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ रही है।

एयरफोर्स जॉब्स: लोअर डिवीजन क्लर्क सहित 47 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगी आवेदन प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। आईएएफ ने अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रुप 'सी' के सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी), सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर (नागरिक यांत्रिक परिवहन चालक-साधारण श्रेणी), और हिंदी टाइपिस्ट के कुल 47 पद शामिल हैं।

आईएएफ ने जिन 47 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, उनमें मुख्यालय रखरखाव कमान, भारतीय वायु सेना से 14; मुख्यालय प्रशिक्षण कमान, भारतीय वायु सेना से 05; मुख्यालय केंद्रीय वायु कमान, भारतीय वायु सेना से 03; मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना से 06; मुख्यालय पूर्वी वायु कमान, भारतीय वायु सेना से 06; मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना से 05; मुख्यालय दक्षिणी वायु कमान, भारतीय वायु सेना से 01; और स्वतंत्र इकाइयां, भारतीय वायु सेना से 07 पद शामिल हैं।

पाकिस्तान सीमा पर पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, 585 स्थानों पर लगाए 2,291 सीसीटीवी कैमरे

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए 585 स्थानों पर कुल 2,291 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसे राज्य की 'दूसरी सुरक्षा पंक्ति' के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे संवेदनशील गांवों और आवाजाही वाले मार्गों पर सघन निगरानी रखी जा सके।

यह कदम 'गैंगस्टरन ते वार' अभियान के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क की सप्लाई चेन को तोड़ना है।

जहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहा है, वहीं पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि यदि कोई तस्करी का सामान सीमा पार कर भी जाए, तो वह राज्य के भीतर आगे न बढ़ सके।

पुलिस ने बताया कि सीमा से जुड़े जिलों के 41 थानों को भी सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था और मजबूत हुई है। राज्य में लगाए गए नाकों को अब अधिक प्रभावी और अप्रत्याशित बनाया गया है। वाहन जांच अब केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर लक्षित कार्रवाई की जा रही है।

सीमा से सटे जिलों में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए एंटी-ड्रोन निगरानी भी तेज कर दी गई है।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुहैल कासिम मीर ने कहा कि दूसरी सुरक्षा पंक्ति वह स्तर है जहां अपराध की कड़ी को प्रभावी ढंग से तोड़ा जाता है। यदि सीमा पर कोई सेंध लगती भी है तो पुलिस अपने क्षेत्राधिकार में उसे तुरंत रोकने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि गांव स्तर की रक्षा समितियों और स्थानीय नेटवर्क को भी सुरक्षा ढांचे से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि दूसरी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करना राज्य की एंटी-गैंगस्टर रणनीति का अहम हिस्सा है। हमारा लक्ष्य सीमा पार सप्लाई से लेकर अंतिम डिलीवरी तक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई तस्करी या अपराध की कोशिश होती है तो उसे शुरुआती स्तर पर ही पकड़कर तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा।

सौतेले पिता ने 14 वर्षीय बेटी की हत्या कर शव झाड़ियों में छिपाया, गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर के जेवर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव भी बरामद कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रोही आरआर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र पुत्र गौरी प्रसाद ने 21 अप्रैल को थाना जेवर में एक प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी पुत्री अंजली (उम्र करीब 14 वर्ष) 20 अप्रैल को दूध लेने के लिए दुकान पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पाया।

इस सूचना के आधार पर थाना जेवर में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस द्वारा की गई गहन विवेचना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि मृतका अंजली का अपने सौतेले पिता सुरेंद्र के साथ अक्सर विवाद होता रहता था।

इसी विवाद के चलते सुरेंद्र ने 20 अप्रैल को अंजली के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने घबराकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और कानीगढ़ी व जेवर खादर के बीच यमुना पुस्ता रोड स्थित शीशम की झाड़ियों में शव को छिपा दिया।

मध्य प्रदेश में रेल सुरक्षा की बनी रणनीति, व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर

भोपाल। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले विस्तृत रेल नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की रणनीति बनाई गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में राज्य रेल सुरक्षा उच्चस्तरीय समन्वय समिति की बैठक पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले विस्तृत रेल नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय बढ़ाना तथा आगामी बड़े आयोजनों के दृष्टिगत रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करना था। पुलिस महानिदेशक मकवाणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर पूर्व तैयारी, सतत निगरानी एवं त्वरित समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने विशेष रूप से सिंहस्थ-2028 के विशाल आयोजन को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति तैयार करने पर बल दिया। बैठक में रेलवे के सुगम एवं सुरक्षित संचालन हेतु सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के मध्य समन्वय, रेलवे परिक्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, रेलवे ट्रैक को अवरोधमुक्त रखने, भीड़ नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षा, महिला एवं वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी तथा संवेदनशील स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त आगामी सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए रेल यातायात, यात्री दबाव, अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, स्टेशन प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था तथा बहु-एजेंसी समन्वय की प्रारंभिक रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया।

यह बैठक राज्य एवं केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख रेल कॉरिडोर का केंद्र है, ऐसे में विभिन्न राज्यों एवं रेलवे जोन के साथ समन्वय से अपराध नियंत्रण, ट्रैक सुरक्षा, यात्री सुरक्षा तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी।

झीलों-नदियों से पहाड़ों तक, ऐसे लिखें पृथ्वी की खूबसूरती पर अपना नाम, नासा के मजेदार लैंडसेट सर्विस के लिए फॉलो करें ये स्टेप

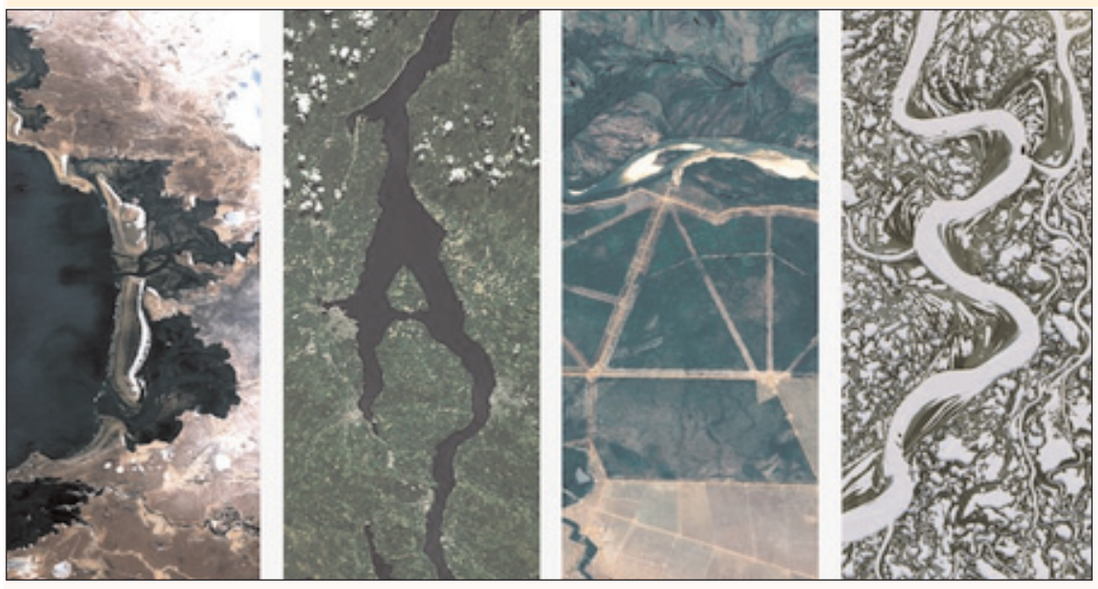

नई दिल्ली। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक रोचक और अनोखी शुरू की गई सर्विस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब आप अपनी पसंद का नाम लैंडसेट उपग्रह की तस्वीरों में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे झीलें, नदियों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर देख सकते हैं।

नासा की यह सर्विस 'योर नेम इन लैंडसेट' नाम से शुरू की गई है। इसमें यूजर्स अपना नाम अंग्रेजी अक्षरों में टाइप करते हैं और सिस्टम अपने आप नाम के हर अक्षर को लैंडसेट सैटेलाइट द्वारा ली गई असली धरती की तस्वीरों से मिलाकर एक सुंदर ग्राफिक बना देता है। लैंडसेट कार्यक्रम 50 वर्ष से अधिक पुराना है और यह पृथ्वी की निगरानी के लिए सबसे लंबे समय से चल रहे उपग्रह कार्यक्रमों में से एक है। इन तस्वीरों में इस्तेमाल की गई छवियां नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी, नासा वर्ल्ड व्यू, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर और ईएए सेंटीनल हब से ली गई हैं।

यह इंटरैक्टिव टूल न सिर्फ मनोरंजन के लिए है, बल्कि लोगों को लैंडसेट कार्यक्रम और पृथ्वी के बारे में जागरूक करने का भी एक अच्छा माध्यम है। हर अक्षर के लिए अलग-अलग प्राकृतिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो पृथ्वी की विविधता को दिखाता है।

नासा का कहना है कि यह सेवा पृथ्वी की सुंदरता को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें सैटेलाइट इमेजरी से जोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास भी है।

अब सवाल है कि अपना नाम लैंडसेट पर कैसे देखें? तो इसके लिए नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से जानकारी दी गई है। इसके लिए सबसे पहले नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 'योर नेम इन लैंडसेट' पेज पर जाएं। वहां अपना नाम दर्ज करें, वहां दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों (ए-जेड) में टाइप करें।

इसके बाद एंटर बटन दबाएं या सब्मिट पर क्लिक कर जनरेट करें। इसके कुछ ही सेकंड में आपके नाम के अक्षर पृथ्वी की खूबसूरत भौगोलिक विशेषताओं जैसे नीली झीलें, हरे-भरे क्षेत्र, रेगिस्तानी पैटर्न या बर्फ से ढके पहाड़ से बने हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बनी हुई इस खास कलाकृति को डाउनलोड करके सेव या शेयर भी कर सकते हैं।

क्या खाना छोड़ने से कम होता है वजन, जानें सेहत को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली। बढ़ता वजन सेहत के लिए न केवल खतरनाक बल्कि कई बार लोगों को इसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ जाता है। वजन कम करने के लिए लोग जिम से लेकर कई जतन करते हैं। कई लोग तो भोजन छोड़ने की गलती तक कर बैठते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भोजन और वजन को लेकर फैले आम मिथकों और वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। संगठन के अनुसार, खाना छोड़ना वजन घटाने का सही तरीका नहीं है, बल्कि इससे उल्टा नुकसान हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया कि भोजन छोड़ने से अस्थायी रूप से वजन कम लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह तरीका असफल साबित होता है। जब कोई व्यक्ति भोजन छोड़ता है तो बाद में ज्यादा भूख लगने के कारण अधिक खाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कुल कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है और वजन घटाने के बजाय बढ़ने का खतरा रहता है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, भोजन छोड़ने से शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे आम प्रभाव थकान महसूस होना है। ऊर्जा की कमी के कारण दिनभर सुस्ती बनी रहती है। साथ ही ब्लड शुगर का स्तर अचानक गिर सकता है, जिससे लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थिति बन सकती है। इससे चक्कर आना, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत जैसी परेशानियां होती हैं।

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए नियमित और संतुलित भोजन जरूरी है।

भोजन छोड़ने की बजाय छोटे-छोटे अंतराल पर पौष्टिक भोजन लेना बेहतर है। इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, ऊर्जा का स्तर बना रहता है और अनावश्यक भूख नहीं लगती।विशेषज्ञों का मानना है कि वजन कम करने का सबसे सही तरीका कुल कैलोरी इनटेक को नियंत्रित करना, स्वस्थ आहार चुनना और नियमित शारीरिक व्यायाम करना है।

केवल भोजन छोड़कर वजन घटाने की कोशिश न सिर्फ असफल होती है, बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में वजन घटाने से संबंधित किसी भी मिथक पर भरोसा न करें। इसके बजाय वैज्ञानिक तथ्यों और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर आहार योजना बनाएं। खासकर युवा और कामकाजी लोग जो व्यस्तता में भोजन छोड़ देते हैं, उन्हें इस आदत को तुरंत बदलना चाहिए।

'पिनव्हील गैलेक्सी' क्या है? नासा ने दिखाई 25 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्पेस की खूबसूरत झलक

नई दिल्ली। ब्रह्मांड की अनंत सुंदरता को करीब से देखने का एक और शानदार अवसर नासा ने प्रदान किया है।

नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर पिनव्हील गैलेक्सी के केंद्र की आश्चर्यजनक तस्वीर कैद की है। यह तस्वीर हाल ही में ली गई, जिसमें गैलेक्सी की चमक साफ नजर आ रही है।

पिनव्हील गैलेक्सी यह एक विशाल सर्पिल आकार की आकाशगंगा है, जिसे वैज्ञानिक मेसियर 101 यानी एम-101 के नाम से भी जानते हैं।

इसका आकार ठीक पिनव्हील (चर्खी) जैसा है, इसलिए इसे पिनव्हील गैलेक्सी कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 25 मिलियन प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है और पृथ्वी से सबसे करीब की 'फेस-ऑन' सर्पिल गैलेक्सिज में से एक है।

'फेस-ऑन' का मतलब है कि हम इस गैलेक्सी को सीधे उसके चेहरे की तरफ से देख सकते हैं। इससे इसके चमकीले केंद्र, सर्पिल भुजाओं और तारों के निर्माण वाले क्षेत्रों को

बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है। इस गैलेक्सी को लेकर खगोलविदों का अनुमान है कि इसमें कम से कम एक ट्रिलियन यानी लगभग 1 हजार अरब तारे मौजूद हैं।

इसके सर्पिल भुजों में बड़े-बड़े स्टार-फॉर्मिंग नेबुला बिखरे हुए हैं, जहां नए तारे लगातार जन्म ले रहे हैं।

नासा की नई जारी की गई तस्वीर में गैलेक्सी का पीला और चमकीला केंद्र साफ दिख रहा है।

इसके चारों ओर नारंगी-भूरी धूल के बादल और गुलाबी रंग के तारों के धब्बे नजर आ रहे हैं। हबल टेलीस्कोप ने अल्ट्रावॉयलेट, विजिबल और नियर-इन्फ्रारेड डेटा प्रदान किया, जबकि जेम्स वेब ने इन्फ्रारेड से धूल और गैस के बीच छिपे रहस्यों को उजागर करने में मदद की।

पिनव्हील गैलेक्सी उत्तरी गोलार्ध में उरसा मेजर तारामंडल में स्थित है, जिसे आम बोलचाल में 'बिग डिपर' भी कहते हैं।

वैज्ञानिक इस गैलेक्सी का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह तारों की आबादी, गैलेक्सी की संरचना और नए तारों के जन्म को समझने में महत्वपूर्ण है।

अनिश्चितता के दौर में मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को मजबूती से नियंत्रित करना आवश्यकः एसबीआई रिसर्च

नई दिल्ली। एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया है कि अगर अमेरिका-ईरान संघर्ष लंबे समय तक अनसुलझा रहता है, तो महंगाई को नियंत्रित करने और विकास में होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्रीय बैंक को मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि अनिश्चितता के समय में, एक अच्छे केंद्रीय बैंक को गलत अनुमानों के प्रति सतर्क, उच्च लागत वाले जोखिमों के खिलाफ मजबूत, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्थित, अनुकूलन के लिए पर्याप्त रूप से लचीला और इतना पारदर्शी होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में अनिश्चितता स्वयं केंद्रीय बैंक के बारे में अनिश्चितता न बन जाए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्या कांति घोष ने कहा, 'यही बात आरबीआई गवर्नर (संजय मल्होत्रा) ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने हालिया भाषण में कही होगी और इसलिए इस संदेश को एक अग्रिम मार्गदर्शन के रूप में भी समझा जा सकता है।'

अनिश्चितता के दौर में मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को मजबूती से नियंत्रित करना आवश्यक है। घोष ने कहा कि वर्तमान समय में सुव्यवस्थित विनिमय दर प्रवाह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पर्याप्त लचीलेपन के साथ एक सुनियोजित पैकेज की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2027 में कुल भुगतान संतुलन (बीओपी) के नकारात्मक (-28 अरब डॉलर) रहने का अनुमान है, साथ ही व्यापार संतुलन के भी नकारात्मक रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वर्ष सकारात्मक प्रवाह की धारणा के आधार पर पूंजी खाते में 26.5 अरब डॉलर का अधिशेष रहने का अनुमान है।

विनिमय दर को हमेशा के लिए झटके को अवशोषित करने वाला तंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं के बढ़ते स्तर के कारण यह आयातित मुद्रास्फीति के एक ऐसे तंत्र में बदल जाती है जो कई चैनलों के माध्यम से रिसकर मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करती है और कई बार विवेकपूर्ण और लचीली मौद्रिक नीति निर्माण के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है।

सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न और दर्द को न करें नजरअंदाज, शरीर दे रहा गंभीर बीमारी का संकेत

नई दिल्ली। कई लोग सुबह उठते समय शरीर में जकड़न और कमर में खिंचाव जैसी समस्या को महसूस करते हैं और इसे आम बात मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर सुबह उठने के बाद जोड़ों की अकड़न लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह शरीर में सूजन, ऑटोइम्यून बीमारी या जोड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।

डॉक्टरों के मुताबिक, जब इंसान सोता है, तब शरीर कई घंटों तक लगभग एक ही स्थिति में रहता है। इस दौरान जोड़ों के बीच मौजूद सिनोवियल द्रव, जो हड्डियों को आसानी से चलाने में मदद करता है, थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। सामान्य स्थिति में जैसे ही शरीर हरकत में आता है, यह द्रव फिर से सामान्य हो जाता है और जकड़न कम होने लगती है। लेकिन अगर शरीर में सूजन या जोड़ों की बीमारी मौजूद हो, तो यह अकड़न लंबे समय तक बनी रह सकती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद चलने-फिरने में काफी परेशानी होती है।

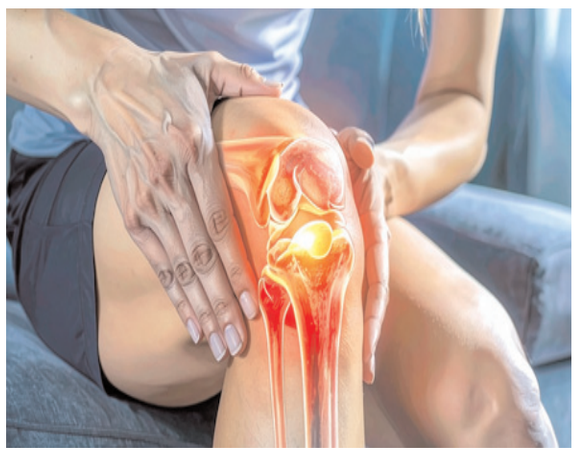

मेडिकल रिसर्च के अनुसार, सुबह लंबे समय तक रहने वाली जकड़न रुमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी का संकेत हो सकती है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इस बीमारी में हाथों और पैरों के जोड़ों में सूजन, गर्माहट और दर्द महसूस हो सकता है। कई मरीजों में सुबह की अकड़न एक घंटे या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है। अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह बीमारी जोड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है।

इसके अलावा, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी सुबह दर्द और जकड़न का बड़ा कारण माना जाता है।

यह बीमारी अधिकतर बढ़ती उम्र में दिखाई देती है। इसमें जोड़ों का कार्टिलेज धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी में इसका असर ज्यादा देखा जाता है। हालांकि इसमें जकड़न अक्सर कुछ मिनटों में कम हो जाती है, लेकिन लगातार दर्द बने रहना चिंता बढ़ा सकती है।

महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है मासिक धर्म, जानें नियमित करने के तरीके

नई दिल्ली । मासिक धर्म को हर महीने होने वाली साधारण प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यह केवल सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिला के शरीर के शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है।

आयुर्वेद में इसे 'आर्तव चक्र' कहा गया है और महिला स्वास्थ्य का मूल आधार माना गया है, लेकिन आज के समय में खराब जीवनशैली की वजह से मासिक धर्म में गड़बड़ी, दर्द होना, पेडू पर सूजन आना, और गर्भाशय में सिस्ट का होना तेजी से बढ़ती समस्याएं बनती जा रही हैं। इससे हार्मोन संतुलन और प्रजनन क्षमता पर फर्क पड़ता है।

चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मासिक धर्म को 'आर्तव प्रवृत्ति' कहा गया है, जो हर महीने 3 से लेकर 5 दिनों तक होता है। हालांकि, जीवन शैली बिगड़ने से मासिक चक्र में गड़बड़ी हो जाती है, और इसके पीछे का कारण है शरीर के तीनों दोष। वात दोष असंतुलन से कमर दर्द और शरीर में ऐंठन बनी रहती है, और पित्त दोष असंतुलन से रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है और शरीर में जलन और गर्मी महसूस होती है, जबकि कफ दोष असंतुलन से शरीर भारी और सुस्त महसूस करता है।

आयुर्वेद में मासिक धर्म को नियमित करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें पहला उपाय है संतुलित आहार। संतुलित आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल खाने की सलाह दी जाती है।

हीट एग्जॉर्शन से हीट स्ट्रोक तक, आयुष मंत्रालय ने बताए गर्मी से बचाव के उपाय

नई दिल्ली। देशभर में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। गर्मी की इस तपिश से लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं। मंत्रालय के अनुसार, गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है, अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो इनसे बचाव संभव है। सबसे पहले तो भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न बनें। यदि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं और पर्याप्त पानी पीकर खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और अपने शरीर के तापमान पर नजर बनाए रखें और जरूरत महसूस होने पर बिना देरी किए चिकित्सक से परामर्श लें।

गर्मी के बढ़ते प्रकोप में सबसे आम समस्या हीट एग्जॉर्शन या गर्मी से थकान और हीट स्ट्रोक है। अगर कोई व्यक्ति अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगे, चक्कर आए, मांसपेशियों में ऐंठन हो, ज्यादा पसीना आए या पसीना आना बंद हो जाए, तो इसे गंभीर लक्षण माना जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट तुरंत कुछ जरूरी उपाय की सलाह देते हैं।

इसके लिए व्यक्ति को तुरंत ठंडी और हवादार जगह पर ले जाएं, शरीर का तापमान बार-बार जांचते रहें, इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, नमक-शक्कर का घोल, छाछ या ओरली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) का सेवन करें। सादा पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स से शरीर को हाइड्रेट रखें।

आईपीएल 2026: एमआई पर भारी पड़ी हेड-क्लासेन की बल्लेबाजी, एसआरएच की 6 विकेट से जीत

मुंबई। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। 9 में से 6 मैच जीतकर एसआरएच प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि एमआई 8 में से 6 मैच गंवाकर 9वें स्थान पर है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस (एमआई) ने 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए। इस टीम को विल जैक्स और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 43 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की। जैक्स 22 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद सूर्यकुमार यादव (5) का विकेट भी गिर गया। टीम ने 110 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया था। यहां से रिकेल्टन ने नमन धीर (22) के साथ 55 रन, जबकि कप्तान हार्दिक पंड्या (31) के साथ 56 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

रिकेल्टन 55 गेंदों में 8 छक्कों और 10 चौकों के साथ 123 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या, साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

इस टीम को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 8.4 ओवरों में 129 रन जोड़े। अभिषेक 24 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ट्रेविस हेड 30 गेंदों में 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए।

इस टीम ने 133 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खो दिया था, जिसके बाद हेनरिक क्लासेन ने नीतीश रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों में 80 रन जुटाकर टीम को 213 के स्कोर तक पहुंचाया। नीतीश 21 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से क्लासेन ने सलिल अरोड़ा के साथ 14 गेंदों में 36 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को बड़ी जीत दिलाई। क्लासेन 30 गेंदों में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 65 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सलिल ने 10 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 30 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से गजनफर ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट निकाला।

दिग्गज गोल्फर विजय कुमार का निधन, पीजीटीआई ने जताया शोक

नई दिल्ली। भारतीय गोल्फ के दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन विजय कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है।

पीजीटीआई ने चार बार के ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता के निधन पर शोक जताते हुए कहा, 'हमें भारतीय गोल्फ के एक सच्चे दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन, विजय कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ है। विजय की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली गोल्फ क्लब में 2002 का इंडियन ओपन जीतना था। उन्होंने स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में खेले गए अल्फ्रेड डनहिल कप 1999 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी असाधारण उपलब्धियां, उनके टैलेंट, सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून का नतीजा हैं, जिन्होंने भारतीय गोल्फ पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।

पीजीटीआई ने कहा, 'अपनी कामयाबियों के अलावा, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले विजय को उनके सकारात्मक रवैये, खुशमिजाज स्वभाव, शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर और खेल भावना के लिए याद किया जाएगा। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के सभी पेशेवर और अधिकारियों की ओर से, हम विजय कुमार के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं। विजय कुमार का जन्म 29 दिसंबर, 1968 को लखनऊ में हुआ था।

महिला टी20 विश्व कप: न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, नेन्सी, इजी को पहली बार मौका

नई दिल्ली । इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की घोषणा के साथ यह भी कंफर्म हो गया है कि विश्व कप के बाद अनुभवी सोफी डिवाइन, ली ताहुहु, और सूजी बेट्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगी।

अमेलिया केर के नेतृत्व में 2024 में खिताब जीतने वाले ग्रुप के मुख्य खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। उस टीम के 10 खिलाड़ी मौजूदा टीम में बरकरार हैं। टीम में नेन्सी पटेल और इजी शार्प को मौका दिया गया है। दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। 21 साल की युवा बल्लेबाज इजी शार्प टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। स्क्वाड में शामिल ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस और डेवोनशायर अपना पहला टी20 विश्व कप खेलेंगे।

हेड कोच बेन सॉयर ने टीम पर भरोसा जताया और डेब्यू करने वाले और जाने वाले दिग्गजों के लिए इस पल की अहमियत पर जोर दिया।

सॉयर ने कहा, 'चुने गए सभी खिलाड़ियों को बधाई। जब भी आपको दुनिया के मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, तो यह एक सम्मान की बात होती है, लेकिन विश्व कप की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इजी और नेन्सी के लिए यह विशेष समय है, क्योंकि यह उनका पहला विश्व कप है।

सॉयर ने टीम के हालिया फॉर्म को एक सकारात्मक संकेत बताया, जिसमें पिछले आठ टी20 मैचों में से सात में जीत मिली है।

उन्होंने कहा, 'हमारे तीन सबसे सीनियर खिलाड़ियों का एक ही टूर्नामेंट में अपना करियर खत्म करना एक बहुत कम मिलने वाला और खास मौका है। तीनों का अपना-अपना करियर शानदार रहा है और उन्होंने इस टीम और आम तौर पर खेल को बहुत कुछ दिया है। टूर्नामेंट के आखिर में इन तीनों को और पहचानने और सेलिब्रेट करने का समय आएगा और मुझे पता है कि अभी वे टीम के साथ अपने आखिरी मिशन में अच्छा परफॉर्म करने पर फोकस कर रहे हैं।'

सॉयर ने कहा, 'मेरा मानना ??है कि हमें एक संतुलित टीम मिली है जिसमें अनुभव और रोमांचक युवा टैलेंट का मिक्स है। हमने पिछले 12 महीनों में अपनी बैटिंग में गहराई विकसित करने के लिए मेहनत की है। इसका नतीजा हमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज में देखने को मिला है। हमारी तेज गेंदबाजी भी शानदार रही है।'

न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में शामिल है। इस ग्रुप की अन्य टीमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हैं।

जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान दौरे के लिए टीम की घोषणा की, नोमवेलो सिबांडा टीम की कप्तानी करेंगी

हरारे । जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नोमवेलो सिबांडा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम में 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे की महिला टीम पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, इसलिए यह दौरा ऐतिहासिक है। जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान में 3 वनडे में और 3 टी20 सीरीज खेलेगी। वनडे 3, 6 और 9 मई को खेले जाएंगे, जबकि टी20 12, 14 और 15 मई को होंगे। सभी मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे।

नोमवेलो को अनुभवी ऑल-राउंडर प्रेशियस मारेंज का सपोर्ट मिलेगा, जिनकी मौजूदगी से टीम को कम अनुभव वाली टीम को गाइडेंस मिलेगी। ऑल-राउंडर केलिस नधलोवू, जिन्हें पिछले महीने न्यूजीलैंड टूर के दौरान कनकशन हुआ था, पूरी तरह से फिट हैं। उनके साथ उभरते हुए खिलाड़ी बिलव्ड बिजा और एडेल जिमुनु को भी टीम में जगह दी गई है। इस टूर के लिए जिम्बाब्वे महिला टीम के तकनीकी निदेशक, स्टीव मैंगोंगो, जो जिम्बाब्वे क्रिकेट के विमेंस हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं, ने कहा कि ये बदलाव सोच-समझकर किए गए और भविष्य के लिए जरूरी भी थे।

मैंगोंगो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'जिम्बाब्वे ने एफटीपी क्रिकेट में एक बड़ा कदम उठाया है, और यह जरूरी है कि हम अपने प्लेयर बेस को बढ़ाते हुए युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर सामने लाएं। महिला टी20 विश्व कप के लिए नेपाल में क्वालिफिकेशन से चूकने के बाद हमने ईमानदारी से देखा कि हम कहां हैं। नई रणनीति की वजह से, जिम्बाब्वे कई अनुभवी नामों के बिना होगा। जोसेफिन नकोमो और न्याशा ग्वानजुरा चोट की वजह से बाहर हैं, जबकि चिपो मुगेरी-तिरिपानो निजी प्रतिबद्धताओं की वजह से उपलब्ध नहीं हैं।

फीफा और एएफसी ने अफगान महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लेने की इजाजत दी

वैंकूवर। फीफा काउंसिल ने बुधवार को फीफा गवर्नेंस रेगुलेशंस में एक बदलाव को मंजूरी दी, जिससे अफगान महिला खिलाड़ी फीफा कॉम्पिटिशन के हिस्से के तौर पर आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले सकेंगी।

अफगानिस्तान की महिला टीम ने 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी मैच नहीं खेला है। इस ऐतिहासिक फैसले का आखिरी लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों को उनके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से बाहर न किया जाए।

फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'फीफा काउंसिल ने आज फीफा गवर्नेंस रेगुलेशंस में एक अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिससे अफगान महिला खिलाड़ी—जिसमें फीफा द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली और फीफा-समर्थित अफगान महिला यूनाइटेड टीम की सदस्य भी शामिल हैं—संबंधित लोकल कॉन्फेडरेशन, इस मामले में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के साथ अनुबंध में फीफा कॉम्पिटिशन के हिस्से के तौर पर आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी।

फीफा से वित्तपोषित और समर्थित टीम अपना अगला ट्रेनिंग कैंप 1 से 9 जून तक न्यूजीलैंड में लगाएगी, जहां उन्हें कुक आइलैंड्स के खिलाफ खेलने का मौका भी मिलेगा।

हालांकि यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है, लेकिन फीफा अब जरूरी प्रशासनिक और तैयारी के कदम उठाएगा, जिसमें टीम रजिस्ट्रेशन और एक ऑपरेशनल और स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना शामिल है। फीफा ने एक रिलीज में कहा, 'विश्व फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए एक सुरक्षित, पेशेवर और टिकाऊ रास्ता पक्का करने के लिए सभी जरूरी स्त्रोत - इंसानी, तकनीकी और वित्तीय - देगी।

अफगान महिला यूनाइटेड प्लेयर्स के लिए सपोर्ट पैकेज पूरे ट्रांजिशन फेज में दो साल तक जारी रहेंगे। इससे नए स्ट्रक्चर को सुरक्षा के प्रदर्शन के सबसे ऊंचे मानक बनाए रखते हुए विकसित करने में मदद मिलेगी।

अफगानिस्तान की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, इन खिलाड़ियों के लिए, अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करना पहचान, सम्मान और उम्मीद के बारे में है। फीफा नेतृत्व का शुक्रिया, जिसने उनका सबसे बड़ा अनुरोध सुना और ऐसा हल दिया जो किसी दूसरे खेल ने कभी हासिल नहीं किया। यह पल यह भी दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

फीफा प्रमुख इन्फेंटिनो ने पीएम मोदी के सिक्किम फुटबॉल सेशन की तारीफ की

नई दिल्ली। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल के प्रति लगाव की तारीफ की और सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए पीएम की एक फोटो शेयर की।

दक्षिण एशिया में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने की अपनी कोशिशों के लिए मशहूर फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने अपने इंस्टाग्राम पर पीएम की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'पीएम मोदी को हमारा खूबसूरत खेल खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। फुटबॉल सच में दुनिया को जोड़ता है। मंगलवार को पीएम मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला, और इसे एक प्यारी सुबह और ऊर्जावान सेशन बताया था। पीएम मोदी ने एक्स पर कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था, 'सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गंगटोक की एक प्यारी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं। एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, 'युवाओं के साथ एक ऊर्जावान फुटबॉल सेशन। फीफा अध्यक्ष और पीएम मोदी पूर्व में कई बार अंतरराष्ट्रीय फोरम पर मिल चुके हैं। उनकी सबसे खास मुलाकातें दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में जी-20 समिट में और फिर दिसंबर 2024 में कुवैत में हुईं। अर्जेंटीना में जी-20 समिट में मीटिंग के दौरान, फीफा अध्यक्ष ने पीएम मोदी को उनके नाम वाली एक फुटबॉल जर्सी गिफ्ट की।

मैड्रिड ओपन: हैली बैप्टिस्ट ने एरिना सबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

मैड्रिड । अमेरिका की हैली बैप्टिस्ट ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एरिना सबालेंका को हराकर मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

24 साल की हैली ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी की और छह मैच पॉइंट बचाकर दो घंटे 30 मिनट तक चले मुकाबले में 2-6, 6-2, 7-6(6) से जीत हासिल की। ??यह जीत न सिर्फ उनके करियर की सबसे बड़ी जीत थी, बल्कि टूर पर सबालेंका की 15 मैचों की जीत का सिलसिला भी खत्म हो गया।

बैप्टिस्ट, जिन्होंने इस हफ्ते से पहले कभी किसी टॉप 5 अपोनेंट को नहीं हराया था, ने अब मैड्रिड में टॉप-टियर प्लेयर्स पर लगातार दो जीत दर्ज की हैं। इससे पहले उन्होंने तीसरे राउंड में जैस्मीन पाओलिनी को बाहर किया था।

बैप्टिस्ट का सेमीफाइनल में सामना नौवीं सीड मीरा एंड्रीवा से होगा। बैप्टिस्ट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने कुछ सप्ताह पहले उनके खिलाफ खेला था, और वह एक करीबी मैच था। मैं हर सेट में सिर्फ एक बार टूटी। इसलिए मुझे बेहतर अंदाजा हो गया था कि उसे कैसे खेलना है, और मुझे कैसे खेलना चाहिए, और मुझे क्या बदलाव करने थे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बस अपना गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, वही चीजें कर रही थी जो मैं करती आ रही थी, लेकिन पिछली बार जब हम खेले थे, तब से मुझे कुछ बदलाव करने थे।

उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं जरूरी तौर पर गली के बाहर गेंद मारने पर काम कर रही हूं। लेकिन जाहिर है जब आप हर समय पॉइंट्स खेल रहे होते हैं तो आप उन पोजीशन में आ जाते हैं। मुझे सच में उन पोजीशन में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वहां शॉट बना सकती हूं।

सबालेंका ने कहा, 'बैप्टिस्ट ने बहादुरी वाला खेल दिखाया। मुझे लगता है कि मियामी में मैंने उसे ज्यादा मौके नहीं दिए।

पीएसजी बनाम बायर्न: पेरिस सेंट-जर्मेन को मिली मामूली बढ़त

पेरिस । पेरिस सेंट-जर्मेन और बायर्न म्यूनिख के बीच खेला गया मुकाबला 5-4 के रोमांचक स्कोरलाइन के साथ समाप्त हुआ। इस मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से बेहतरीन अटैक देखने को मिला।

मैच की शुरुआत से ही लगने लगा था कि दोनों टीमें आक्रामक रुख अपनाएंगी। हैरी केन ने पेनल्टी के जरिए बायर्न को शुरुआती बढ़त दिलाई। यह बढ़त ज्यादा देर टिक नहीं सकी। ख्विचा क्वारत्सखेलिया ने शानदार, बेहतरीन कौशल दिखाते हुए बराबरी का गोल दागा।

पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच लगातार जवाबी हमले होते रहे। जोआओ नेवेस के हेडर ने पीएसजी को बढ़त दिलाई, लेकिन माइकल ओलिस ने एक शानदार सोलो रन के बाद गोल कर बायर्न को फिर बराबरी पर ला दिया। हाफ खत्म होने से ठीक पहले उस्मान डेम्बेले ने पेनल्टी पर गोल कर पीएसजी को 3-2 की बढ़त दिलाई।

दूसरे हाफ में कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पीएसजी मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा। अशरफ हकीमी के शानदार क्रॉस पर क्वारात्सखेलिया ने अपना दूसरा गोल किया, और फिर डेम्बेले ने भी एक और गोल जोड़कर स्कोर 5-2 कर दिया। इस समय पीएसजी का आक्रमण बेहद संगठित और घातक दिख रहा था।बायर्न म्यूनिख के लिए दयोत उपामेकानो ने हेडर के जरिए एक गोल किया और इसके तुरंत बाद लुइस डियाज ने शानदार स्ट्राइक लगाकर स्कोर 5-4 कर दिया। इस वापसी ने मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा।

पीएसजी के कोच लुइस एनरिक ने मैच के बाद कहा कि यह मुकाबला किसी भी दिशा में जा सकता था, जो इस खेल की गुणवत्ता को दर्शाता है। वहीं, डेम्बेले ने भी माना कि दोनों टीमें आक्रामक खेल में विश्वास रखती हैं और दूसरे लेग में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिल सकता है।

अब जब दोनों टीमें दूसरे लेग के लिए एलियांज एरिना में उतरेंगी, तो उम्मीद की जा रही है कि यह मुकाबला फिर से फुटबॉल प्रेमियों को एक और क्लासिक देखने का मौका देगा।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रीटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415